● वर्ष-4
● अंक-108
रायपुर, रविवार
15 दिसंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» भारतीय संविधान न सिर्फ सबसे...

नेहरू से राहुल तक, लोस में गांधी परिवार पर जमकर बरसे मोदी

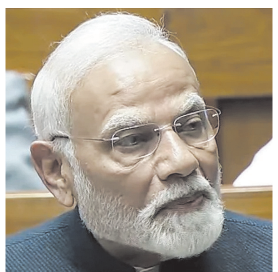

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि भारत का गणतांत्रिक अतीत विश्व के लिए प्रेरक रहा है और इसलिए देश को लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि जब हम संविधान लागू होने के 75 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं तो अच्छा संयोग है कि राष्ट्रपति पद पर एक महिला आसीन हैं जो संविधान की भावना के अनुरूप भी है। मोदी ने कहा कि भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में बहुत मजबूत कदम रख रहा है और 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प उसे स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक विकसित भारत बनाने का है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के निर्णयों में लगातार भारत की एकता को मजबूती देने का प्रयास किया जाता रहा है, अनुच्छेद 370 एकता में रुकावट बना हुआ था और इसलिए हमने जमीन में गाड़ दिया।

मोदी ने कहा कि हमने संविधान की एकता की भावना के अनुरूप नई शिक्षा नीति में मातृको बहुत बल दिया है और अब गरीब परिवार के बच्चे मातृमें पढ़ाई करके डॉक्टर-इंजीनियर बन सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, इस परिवार ने हर स्तर पर संविधान को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता ये भारत की विशेषता रही है और इस देश की प्रगति भी विविधता को सेलिब्रेट करने में है। लेकिन गुलामी की मानसिकता में पले-बढ़े लोगों ने, भारत का भला न देख पाने वाले लोगों ने... वो विविधता में विरोधाभास ढूढंते रहे। इतना ही नहीं, विविधता जो हमारा अमूल्य खजाना है उसको सेलिब्रेट करने के बजाय उस विविधता में ऐसे जहरीले बीज बोने के प्रयास करते रहे, ताकि देश की एकता पर चोट पहुंचे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 1952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था। राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं थे, जनता का कोई आदेश नहीं था। उसी दौरान उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, %अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1951 में ये पाप किया गया लेकिन देश चुप नहीं था। उस समय के राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें चेताया कि ये गलत हो रहा है...लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावकों की सलाह मानी नहीं। ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय-समय पर वो संविधान का शिकार करती रही।

अन्य कार्यवाही- केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने शनिवार को लोकसभा में कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर किसी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचे। उन्होंने सदन में 'भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा' पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए जिस तरह के सुरक्षात्मक उपाय हैं, उतने किसी दूसरे देश में नहीं है।

वहीं, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता ए राजा ने शनिवार को केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तो देश में आपातकाल लगाकर केवल लोकतंत्र को आघात पहुंचाया, लेकिन इस सरकार ने संविधान की मूल संरचना के सभी तत्वों पर आक्रमण किया है।

प्रदेश में विकास की रफ्तार भी डबल

केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका की ओर छत्तीसगढ़

रायपुर। केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में विष्णु देव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ की जनता को दोहरा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने जिस संकल्प के साथ विकसित भारत की प्रतिबद्धता जाहिर की उसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ में भी जनहित कार्यों का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। साय सरकार में गुणवत्ता, जवाबदेही और पारदर्शिता के तीन कार्यस्तम्भ के जरिए लोगों तक सुशासन का संदेश जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संचालित योजनाओं का छत्तीसगढ़ को भरपूर लाभ मिल रहा है। केन्द्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन और उनका लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने में छत्तीसगढ़ लगातार अग्रणी भूमिका की ओर बढ़ रहा है। जिनमें पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से पूरे देश में सर्वाधिक 8.46 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य मिला है। मोदी जी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति के साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वे के पात्र 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को भी पक्का मकान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब तक पीएम आवास योजना ग्रामीण में 1 लाख 74 हजार 585 हितग्राहियों को उनका आवास मिल चुका है।

प्रदेश में पिछड़ी जनजाति समुदाय के लोगों को पीएम जनमन योजना का भी लाभ मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों के 24 हजार 542 परिवारो को आवास की स्वीकृति मिल चुकी है। प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा 1 हजार 699 करोड़ की स्वीकृति से 2 हजार 449 किलोमीटर की 715 सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा, जिनसे 777 पीव्हीटीजी बसाहटें लाभान्वित होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रही है। प्रदेश में लोगों को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ मिल रहा है, इस उपलब्धि के लिए भारत द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्य के 266 सरकारी अस्पतालों को क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी दिया है। छत्तीसगढ़ में 11 लाख 20 हजार से ज्यादा मरीज आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित हुए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिसम्बर 2023 से नवम्बर 2024 तक 883 संविदा पदों पर नियुक्ति भी दी गई है। डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार भी डबल हो गई है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित दूरस्थ इलाकों में 103 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें बन चुकी हैं, इनमें 616 सड़कों के नवीनीकरण का कार्य भी जारी है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4500 करोड़ रूपए के प्रावधान के साथ ही छत्तीसगढ़ के 50 लाख परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुँचाने का लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए 40 लाख परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचा दिया गया है।

नेशनल लोक अदालत में 22 लाख 59 हजार से अधिक प्रकरणों का हुआ रिकार्ड निराकरण

842 करोड़ रूपए से अधिक का अवार्ड पारित

रायपुर। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आज छत्तीसगढ़ राज्य में 22 लाख 59 हजार से अधिक प्रकरणों का रिकार्ड निराकरण हुआ। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कुल 842 करोड़ रूपए से अधिक का अवार्ड पारित किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि आज 14 दिसम्बर को उच्च न्यायालय से लेकर तालुका स्तर न्यायालयों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन हुआ। हाईकोर्ट बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश ने नेशनल लोक अदालत के तहत खण्डपीठों का वर्चुअल निरीक्षण किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह इस वर्ष की चतुर्थ एवं अंतिम नेशलन लोक अदालत थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा रायपुर व दुर्ग के लोक अदालत की कार्यवाहियों का निरीक्षण कर वहां के प्रधान जिला न्यायाधीशों से चर्चा की गई और उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। इससे लोक अदालत के पीठासीन अधिकारियों, सदस्यों व पक्षकारों को प्रोत्साहन मिला और पक्षकारों में विश्वास सृजित हुआ है। लोक अदालत की विश्वसनीयता और प्रमाणिकता बढ़ी है। नेशनल लोक अदालत में तकनीकी का उपयोग करते हुए जहां पक्षकार नहीं आ सके, उन्हें वर्चुअल माध्यम से भी जोड़कर तथा मोबाईल वेन के माध्यम से लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण किया गया। गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा नेशनल लोक अदालत की तैयारियों और अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में सभी जिले के प्रधान जिला न्यायाधीशों के साथ बैठक कर सतत् पर्यवेक्षण करते हुए मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा के छत्तीसगढ उच्च न्यायालय में पदभार ग्रहण करने के उपरांत से छत्तीसगढ में शीघ्र सुलभ व सस्ता न्याय की अवधारणा को साकार करते हुए लोगों को लोक अदालत के माध्यम से त्वरित न्याय प्रदान किया जाना सुनिश्चित हो पा रहा है। मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल को प्रकरणों के निराकरण में उनके सतत् मार्गदर्शन व प्रयास के लिए विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया गया। मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में गठित लोक अदालत की दोनों खण्डपीठों के पीठासीन अधिकारी माननीय न्यायमूर्तिगण व सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया है। मुख्य न्यायाधिपति द्वारा राज्य के सभी सम्मानित प्रधान जिला न्यायाधीशगणों और नेशनल लोक अदालत के संबंध में राज्य में गठित सभी खण्डपीठों के पीठासीन अधिकारियों और खण्डपीठ के सदस्यों, राजस्व अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, सभी न्यायालयीन कर्मचारियों के साथ-साथ सभी पैरालीगल वालेण्टियर, अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा पक्षकारों तथा अन्य सभी लोगों, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस नेशनल लोक अदालत को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने में योगदान दिया है, को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

केंद्रीय गृहमंत्री शाह आज बस्तर प्रवास पर

बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में होंगे शामिल

रायपुर/ जगदलपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रविवार को बस्तर प्रवास पर पहुंचेंगे, जहां वे बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। साथ ही वे बस्तर में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियानों की समीक्षा करने के साथ ही दूसरे दिन 16 दिसंबर को सुबह में नक्सली हमले में वीरगति को प्राप्त दो जवानों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। वहीं नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों के साथ रात्रि भोज भी करेंगे। बस्तर संभाग के किसी कैंप में रात बिताएंगे। सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि केंद्रीय गृहमंत्री बस्तर के खूंखार नक्सली हिड़मा के गांव पूवर्ती में वो रात गुजार सकते हैं। उनके अबूझमाड़ या पूवर्ती गांव के किसी कैंप में रुकने की खबर है। हालांकि इस खबर की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। यदि ऐसा हुआ था वे ऐसा करने वाले देश के पहले केंद्रय गृहमंत्री बन जायेंगे। विदित हो कि चार महीने पहले प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा खूंखार नक्सली हिड़मा के गांव पूवर्ती गये थे। गृहमंत्री के प्रवास को देखते हुए एयरपोर्ट सहित नगर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान 15 दिसम्बर को स्टेडियम को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, और एसपीजी सुरक्षा की कमान संभाल रही है। यह दूसरा मौका है जब देश के गृहमंत्री बस्तर में अपने 1 दिन गुजारेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए जगदलपुर एयरपोर्ट से लेकर जहां-जहां गृहमंत्री का कार्यक्रम होना है वहां सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किये जा रहे हैं। गृहमंत्री के प्रवास को देखते हुए सेंट्रल आर्म्स फोर्स, सीआरपीएफ और बस्तर पुलिस के भी जवानों को चप्पे-चप्पे पर तैनात किया जा रहा है। साथ ही पूरे बस्तर संभाग में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सभी थाना, पुलिस कैंप और पुलिस चौकी को भी अलर्ट किया गया है। इसके अलावा इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम को चारों तरफ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है, वहीं बस्तर संभाग के अन्य इलाकों में नक्सलियों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। विशेष विमान से दिल्ली से जगदलपुर पहुंचने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को कई लेयरों में सुरक्षा मुहैया करवाए जाने की तैयारी भी की जा रही है। इसके तहत पैरामिलेट्री व स्थानीय पुलिस के जवानों को बाहरी लेयरों में सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी, वहीं शाह के सबसे करीब के स्तर पर उनकी अपनी जेड प्लस सुरक्षा रहेगी, जो उन्हें घेरकर चलती रहेगी। इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में सैकड़ों जवानों को तैनात किए जाने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ प्रवास के तय कार्यक्रम के अनुसार 14 दिसंबर की रात 9 बजे दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे, 14 दिसंबर को वह रात्रि विश्राम करेंगे। 15 दिसंबर की सुबह अमित शाह पुलिस परेड ग्राउंड में प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवॉर्ड में शमिल होंगे।

विदेश में पढ़ते हैं नक्सलियों के बच्चे यहां करते हैं स्कूल का विरोध: विजय

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। विजय शर्मा जगदलपुर बस्तर ओलंपिक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे।इस दौरान उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के दौरे और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी साझा की।साथ ही साथ नक्सलवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी।

विजय शर्मा ने कहा कि नक्सली अपने बच्चों की खूब चिंता करते हैं।इसलिए वो विदेश के बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन अंदरुनी क्षेत्रों में स्कूल भी खोलने नहीं देते।विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर के जंगलों में मुखबिरी और नक्सल हिंसा के कारण ना जाने कितनी ही हत्याएं हो चुकी हैं। जो हमारे सामने नहीं आएं।

विजय शर्मा ने कहा ये वो हत्याएं हैं जो लोगों के सामने निकलकर आई है। और ना जाने ऐसी कितनी हत्याएं बस्तर के जंगलों हुई है। नक्सलियों के बच्चे विदेशों के बड़े स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। लेकिन बस्तर में नक्सली स्कूल खोलने नहीं देते।

इससे पहले गृहमंत्री विजय शर्मा ने संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की। इस दौरान विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों तेलंगाना, ओड़िशा, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, असम जैसे कई राज्यों से ऐसे लोग भी बस्तर पहुंचे हैं। जिन्होंने मुख्यधारा में शामिल होकर समाज में एक ओहदा पाया है। इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। लोग समझेंगे की मुख्य धारा में शामिल होकर भी बेहतर कार्य किया जा सकता है।

विजय शर्मा ने कहा 15 दिसंबर को बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दोपहर ढाई बजे शामिल होंगे। इसके बाद नक्सलियों की ढ्ढश्वष्ठ ब्लास्ट की चपेट में आकर दिव्यांग हुए लोगों से उनकी मुलाकात होगी। ऐसे दिव्यागों के लिए भी पैरा ओलंपिक की शुरुआत 15 दिसम्बर से की जा रही है। इसके अलावा अमित शाह फोर्स के उन कमांडर्स से भी मिलेंगे। जिन्होंने नक्सलियों के खिलाफ अभियानों में बेहतर काम किया है। अमित शाह रात्रि विश्राम जगदलपुर में ही करेंगे। अगले दिन 16 दिसंबर की सुबह अमित शाह जगदलपुर की अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। शहीद परिवार से मुलाकात भी करेंगे। अमित शाह एक कैंप का दौरा करके जवानों से मुलाकात करेंगे।

धान मिसाई के दौरान ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन में लगी आग

बलरामपुर। धान मिसाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां धान मिसाई कर रहे ट्रैक्टर और थ्रेसर में अचानक आग लग गई। जिससे ट्रैक्टर और थ्रेसर जलकर खाक हो गए। वहीं आग लगने से फसलों को भी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि दहेजवार में किसान के खलिहान में धान की मिसाई की जा रही थी। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नही हो पाई है। घटना बलरामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र की है।

जानकारी मुताबिक, खेत में धान मिसाई कर रहे ट्रैक्टर और थ्रेसर में आग लग गई। पहले ट्रैक्टर के इंजन में आग लगी, जिसके बाद ,फसल भी जलकर खाख हो गई। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि इंजन में शार्ट शार्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं राजस्व की टीम आगजनी से हुए क्षति का आंकलन करने में जुटी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।

अवैध धान भंडारण पर राजस्व विभाग की छापेमारी, 282 क्विंटल धान जब्त

मुंगेली। प्रदेश में इन दिनों समर्थन मुल्य में किसानों से धान खरीदी की जा रही है। मुंगेली जिले में भी धान की खरीदी जोर-शोर से चल रही है, खासकर वनांचल क्षेत्र और खुड़िया धान खरीदी केंद्र में धान की बंपर आवक हो रही है। हालांकि, कुछ खरीदी केंद्रों पर बिचौलियों द्वारा धान का अवैध भंडारण किए जाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं।

हर साल आती हैं गड़बड़ी की शिकायतें

लोरमी तहसील अंतर्गत डोंगरिया और खुड़िया धान खरीदी केंद्रों में कई वर्षों से धान खरीदी में गड़बड़ी की शिकायतें मिल चुकी हैं। बिचौलिये सैकड़ों किसानों की पर्चियों को गिरवी रखकर फर्जी तरीके से धान की बिक्री करते हैं, जिस पर कई बार जांच और कार्रवाई भी की जा चुकी है। इस बार भी जब वनांचल क्षेत्र में धान खरीदी की शुरुआत हुई, तो बिचौलिये फिर से सक्रिय हो गए हैं और अवैध रूप से धान का भंडारण कर रहे हैं।

कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई

मुंगेली कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर, राजस्व विभाग की टीम ने वनग्राम मंजुरहा में अवैध धान संग्रहण की सूचना पर छापेमारी की। यहां, मुन्ना यादव के घर में 705 बोरी यानी 282 क्विंटल धान का अवैध भंडारण पाया गया। इसके बाद, राजस्व अधिकारियों ने मौके से धान जब्त कर लिया।

इस छापेमारी में नायब तहसीलदार चंद्रप्रकाश सोनी, शांतनु तारम और अन्य अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर के निर्देशानुसार, जिले के दुल्लापुर बेरियर पर भी अवैध धान परिवहन की जांच की गई। वहां सभी वाहनों, टोकन और पर्ची पट्टे की सही स्थिति पाई गई, जिसके बाद वाहनों को एंट्री दी गई। इसके साथ ही बिजराकछार जंगल क्षेत्र से लगे बेरियर पर भी निरीक्षण किया गया, ताकि अवैध धान परिवहन को रोका जा सके।

लोरमी के एसडीएम अजीत पुजारी ने इस छापेमारी की पुष्टि करते हुए बताया कि 282 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आगे भी सूचना मिलने पर ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी।

संबलपुरी गांव में हाथी ने दी दस्तक, दहशत में गांव के लोग

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से लगे हुए संबलपुरी गाँव मे शुक्रवार की शाम उस समय अफरा तफरी की स्थित निर्मित हो गई जब जंगलों से निकल कर एक हाथी गाँव मे दस्तक देते हुए पुरे गाँव मे दहशत का माहौल निर्मित कर दिया।

मिली जानकारी के मुताबिक इन दिनों रायगढ़ वन मंडल मे कुल 6 हाथी विचरण कर रहे है जिसमे तीन हाथी घरघोड़ा रेंज में और तीन हाथी बंगूरसिया के जंगलों मे विचरण कर रहे है जिन पर वन विभाग की टीम लगातार नजरे बनाये हुए है। शुक्रवार की शाम जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम संबलपुरी मे उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई जब जंगल से निकल कर एक हाथी गाँव के रिहायाशी बस्ती मे दस्तक दे दी।

अचानक हाथी जैसे विशालकाय वन्यप्राणी के गांव पहुंचने से पुरे गाँव मे दहशत का माहौल निर्मित हो गया। बहुत लंबे अरसे बाद हाथी को अपने बीच पाकर गाँव के ग्रामीण दहशत मे रहते हुए भी उसका वीडियो बनाते रहे। इस दौरान हाथी गाँव मे कई जगह नुकसान करता रहा। बताया जा रहा है कि हाथी गांव के एक घर पहुंच गया और वहां रखे कई बोरियों धान को खाकर वापस जंगल में लौट गया है।

इस संबंध में वन विभाग के कर्मचारी ने बताया कि रायगढ़ वन मंडल के जुनवानी परिसर के कक्ष क्रमांक 907 संबलपुरी में एक रास हाथी कल शाम पहुंचा था और हाथी ने यहां रामकुमार भगत, शिवशंकर राठिया के कुछ बोरियों धान को हाथी खाया है वहीं जुनवानी गांव में तरशीला टोप्पो के निर्माणधीन मकान को क्षति पहुंचाया है। यह हाथी अभी संबलपुरी नवागांव के जंगलों में विचरण कर रहा जिससे गांव के ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है।

पोटाश बम से हाथी के शावक की मौत केस में गिरफ्तारी

गरियाबंद। उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में पोटाश बम से घायल हुए हाथी के शावक की मौत मामले में वन विभाग को बड़ी सफलती मिली है। वन विभाग ने 6 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सात दिसंबर को हाथी के शावक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बेबी एलिफेंट 8 नवंबर को पोटाश बम के धमाके में उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में घायल हो गया था। वन विभा को इस केस की जानकारी 10 नवंबर को हुई थी। उसके बाद 27 नवंबर को यह हाथी का शावक वन विभाग को मिला। जिसके बाद उसका इलाज शुरू हुआ। शनिवार 14 दिसंबर को इस केस में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उदंती सीतानदी टाइगर प्रोजेक्ट के उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि पोटाश बम से जो हाथी घायल हुआ था उस बारे में जांच की गई। इसमें गरियाबंद पुलिस का सहयोग लेकर और गोपनीय सूचना के आधार पर तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया। एक आरोपी के घर से सात पोटाश बम बरामद किए गए। तीनों आरोपियों को क्राइम सीन पर ले जाया गया, जहां सीन को रिक्रिएट किया गया।

उपनिदेशक वरुण जैन ने कहा आरोपियों ने खुलासा किया कि 6 नवंबर की शाम को कैसे उन्होंने अलग अलग जगहों पर पोटाश बम लगाया था। आरोपियों ने ये भी बताया कि सात नवंबर को जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो तीन बम उन्हें मिल गए लेकिन एक बम नहीं मिला। जिसके बाद उन्होंने पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें पता चला कि मौके पर खून के धब्बे हाथी के पद चिन्ह मिले। उपनिदेशक ने इस बात की भी जानकारी दी कि तीनों आरोपी अरसी कनहर फरसगांव के रहने वाले हैं। दो आरोपी फरार है।

नशे के खिलाफ पुलिस ने कसा शिकंजा

महिला तस्कर की 35 लाख की संपत्तियां जप्त

बिलासपुर। न्यायधानी पुलिस ने सूखे नशे के खिलाफ अभियान चलाकर तस्करों पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में महिला तस्कर गोदावरी की नशे के अवैध कारोबार से कमाई गई 35 लाख की संपत्ति को जब्त किया गया है। साथ ही इसके चेन को भी तोड़ने का काम कर रही है।

बता दें कि नशीली दवाओं और इंजेक्शन का अवैध कारोबार करने वाली महिला तस्कर की संपत्ति को बिलासपुर पुलिस ने फ्रिज कर लिया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट 1985 के अध्याय ङ्क की धारा 68स्न के तहत कार्रवाई की है। शहर में नशीली दवाएं और इंजेक्शन बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था। वित्तीय जांच में आरोपिया गिन्नी जांगडे उर्फ गोदावरी के नशे के व्यवसाय से कमाई गई रकम की जांच की गई। जिसमें सामने आया कि आरोपिया के बैंक अकाउन्ट पर पिछले 1 वर्षों में करोड़ो का लेनदेन किया गया हैं। महिला नशा तस्कर ने नशे के अवैध कारोबार से संपत्ति बनाई और बीमा पॉलिसी भी खरीदा।

बिलासपुर पुलिस ने महिला नशा तस्कर की 35 लाख से अधिक की संपत्ति को जब्त की है। पूरे नेटवर्क के शुरु से अंत तक जांच के जरिए नशे की चेन को तोड़ने का काम किया गया है।

दरअसल, 21 नवंबर को मिनी बस्ती जरहाभाठा निवासी सृष्टि कुर्रे को 150 नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया था। जांच में पाया गया आरोपियां सृष्टि कुर्रे, गिन्नी जांगडे उर्फ गोदावरी के साथ मिलकर नशे का कारोबार करती थी। जिसके बाद पुलिस ने गिन्नी जांगड़े उर्फ गोदावरी को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पूछताछ में गिन्नी ने बताया कि वह रायपुर के राजधानी मेडिकल और रवि इंटरप्राइजेज से नशीली दवाएं खरीदकर शहर में सप्लाई करती थी। रवि इंटर प्राइजेज के संचालक रवि मरकाम को भी गिरफ्तार किया गया। अपराध में अन्य लोगों की संलिप्ता के संबंध में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (हृष्टक्च) रायपुर से समन्वय स्थापित कर अग्रिम विवेचना की जा रही हैं।

नशे की काली कमाई से बनाई संपत्ति

वित्तीय जांच में आरोपिया गिन्नी जांगडे उर्फ गोदावरी नशे के अवैध कारोबार से कमाई गई रकम की जांच में पता चला कि आरोपिया के बैंक अकाउन्ट पर पिछले 1 वर्षों में करोड़ो का लेनदेन किया गया। जिसका वैध आय का स्त्रोत या अन्य कोई व्यवसाय नही होना पाया गया। आरोपिया गोदावरी ने अमेरी हाफा रोड पर 12 लाख का श्यामा रेसीडेन्सी में फ्लैट खरीदा, सकरी हाफा रोड में 1785 वर्गफुट की भूमि 20 लाख में खरीदा और आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाईफ इंश्योरेंस से 2 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी भी ली। पुलिस ने ये संपत्ति गिन्नी जांगडे उर्फ गोदावरी के अवैध मादक पदार्थ की बिकी से अर्जित राशि से खरीदना पाया।

एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 स्न के तहत संपत्ति को अवैध घोषित करते हुए जब्त किया है। जब्ती की रिपोर्ट तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम कोर्ट मुंबई को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। मुंबई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। एसपी रजनेश सिंह ने एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीबद्ध सभी मामलों में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करने निर्देश का दिया है। अन्य आरोपियो की चल अचल सम्पत्ति की जानकारी एकत्रित कर जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

एनएसएस कैंप में छात्राओं की तबीयत बिगड़ी

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एनएसएस कैंप में शामिल होने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी। जिसके बाद सभी छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस हादसे के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि नगरी के खम्हरिया गांव में लगे एनएसएस कैंप में छात्राओं की तबियत एक के बाद एक बिगड़ गई। सभी को शरीर में अकड़न और बेहोशी की शिकायत हुई। अब तक 10 छात्राओं को नगरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। नगरी के सुखराम नागे शासकीय महाविद्यालय की तरफ से खमहरिया गांव में एनएसएस कैंप लगाया गया। इसमे कुल 50 छात्राओं ने हिस्सा लिया। कैंप 13 दिसंबर तक चलना था। लेकिन एक दिन पहले ही 12 दिसंबर की रात एक दो छात्राओं की तबियत बिगड़ने लगी। इसको कॉलेज प्रबंधन ने हल्के में लिया। लापरवाही दिखाई और फौरन अस्पताल नहीं ले गए। लेकिन जब बीमार छात्राओं की संख्या बढ़ी तब 13 दिसंबर की रात सभी बीमार 10 छात्राओं को नगरी अस्पताल लाया गया।

घर के सामने खड़ी स्कूटी में युवती ने लगाई आग

सरगुजा। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में आज सुबह 5 बजे एक युवती ने चांदनी चौक स्थित घर के सामने खड़ी स्कूटी में आग लगा दी। जब घर के लोग सुबह उठे और बाहर निकलकर देखा तो स्कूटी जलकर खाक हो चुकी है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घर के लोगों ने सीसीटीवी कैमरे की जांच की, जिसमें एक युवती को स्कूटी में आग लगाते हुए देखा गया। युवती ने पास में खड़ी एक और स्कूटी को किनारे कर दूसरी स्कूटी में आग लगाई। पीड़ित ने इस घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी युवती की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस ने 16 लाख का गांजा बरामद किया, आरोपी फरार

बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नगरनार पुलिस ने मादक पदार्थ गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक सिल्वर रंग की महिंद्रा एक्सयूवी से 157 ।96 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 15,79,600 रुपये बताई जा रही है। इसके साथ ही वाहन की कीमत लगभग 10 लाख रुपये है। वहीं आरोपी तस्कर पुलिस को देखते ही घने जंगलों के रास्त भाग निकला। जानकारी के मुताबिक, पुलिस को उड़ीसा से बस्तर की ओर माचकोट और तिरिया के रास्ते गांजा तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद नगरनार थाना प्रभारी टामेश्वर चौहान के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने तस्करी करने वाले आरोपियों की तलाश में घेराबंदी की, लेकिन जैसे ही आरोपी ने पुलिस की टीम को देखा, उसने कार को वहीं छोड़कर घने जंगलों का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस ने इसमें 157 ।96 किलो गांजा बरामद किया है।

आयुक्त ने उप पंजीयक को किया निलंबित

सक्ती। आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी के नाम पर रजिस्ट्री करने के मामले में बिलासपुर कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में उप पंजीयक प्रतीक खेमुका को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि सक्ति में अपने कार्यकाल के दौरान उप पंजीयक ने सक्ती के ग्राम कंचनपुर में एक आदिवासी की 12 डिसमिल जमीन को बिना कलेक्टर की अनुमति के गैर आदिवासी के नाम कर रजिस्ट्री कर दिया था। इसस मामले की शिकायत कलेक्टर से की गई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने प्रतीक खेमुका को दोषी पाते हुए कार्रवाई के लिए राज्य शासन को प्रतिवेदन भेजा था। अब बिलासपुर कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966-9(1) के तहत इस मामले में कार्रवाई की है। निलंबन के बाद प्रतीक खेमुका पर आगे की जांच की प्रक्रिया जारी है।

डीजल ट्रक और पिकअप में आमने-सामने की भिड़ंत

कोरबा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर-अंबिकापुर मार्ग के मोरगा थाना क्षेत्र में आज सुबह-सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तारा घाटी के पास पिकअप वाहन और डीजल ट्रक की आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत में पिकअप ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में पिकअप में सवार चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि ट्रक ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में गाड़ियों में कोई आग नहीं लगी। डीजल टैंक में डीजल होने से बड़ी आगजनी भी होने की संभावना थी, जो टल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मोरगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। इसके साथ ही मर्ग कायम कर मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

डुमरीपालनार में शुरु हुआ जिओ मोबाइल नेटवर्क

■ संचार क्रांति में जुड़ा एक और नया अध्याय

बीजापुर। बीजापुर जिले के अंदुरुनी क्षेत्रों के ग्रामीणों और युवाओं को संचार सुविधा से जोड़ने चलाये जा रहे संचार क्रांति में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। भैरमगढ़ ब्लाक मिरतुर थाना क्षेत्र के अंदुरुनी गांव डुमरीपालनार में जिओ मोबाइल नेटवर्क शुरू कर दिया गया है। डुमरीपालनार में मोबाइल नेटवर्क शुरू होने से इसका लाभ अब इस क्षेत्र के ग्रामीणों व युवाओं को आसानी से मिलना शुरू हो जाएगा।

भैरमगढ़ ब्लॉक के मिरतुर थाना क्षेत्र के अंदुरुनी गांव डुमरीपालनार में नियद नेल्लानार योजना एवं केंद्र की यूएसओएफ योजना के तहत जिओ मोबाईल टावर की स्थापना कर दी गई है। बहुप्रतीक्षित मोबाइल नेटवर्क शुरू होने से डुमरीपालनार सहित तिमेनार व करका के ग्रामीणों व युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। फोर्स की मदद से जिओ मोबाईल नेटवर्क शुरू कर संचार सुविधा का विस्तार किया गया हैं।

संचार क्रांति की इस नई पहल से क्षेत्र के ग्रामीणों को मोबाइल नेटवर्क का लाभ मिलने लगेगा। साथ ही मजबूत नेटवर्क व इंटरनेट की सुविधा से ग्रामीण इलाकों में पढ़ने वाले छात्रों व प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को इससे ऑनलाइन पढ़ाई में फायदा पहुंचेगा। सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस व प्रशासन द्वारा उठाये गए इस महत्वपूर्ण कदम से क्षेत्र में अब संचार की सुविधा बहाल हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों को अब आसानी से अपने परिवार के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

वनरक्षक भर्ती प्रक्रिया में दौड़ लगा रहे अभ्यर्थी की मौत

कोरबा। कोरबा में वन विभाग द्वारा बिलासपुर सर्कल के अंतर्गत आने वाले तीन वन मंडलों के 120 वनरक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया इंदिरा स्टेडियम में जारी है। शनिवार की सुबह भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक अभ्यर्थी की 200 मीटर की दौड़ पूरी करने के बाद अचानक तबियत बिगड़ गई। इस दौरान कुछ देर बाद ही वह नीचे गिर गया और वहां मौजूद मेडिकल की टीम द्वारा फर्स्ट एड देने के बाद उसे मेडिकल अस्पताल भेजा गया। जहां पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वन विभाग ने इस घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी है, जहां उनके आने के बाद वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया संपन्न होगी।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंदिरा स्टेडियम में 4 दिसंबर से वनरक्षक की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। जहां इस कड़ी में शनिवार की सुबह 6 से 8 बजे की पाली में वन विभाग द्वारा भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। जिसमें पड़ोसी जिला जांजगीर चांपा के अकतलरा के ग्राम बाना परसाही निवासी सुख सिंह 26 वर्ष भी पहुंचा था। जहां उसके द्वारा 200 मीटर की दौड़ लगाई गई थी।

दौड़ लगाने के बाद अचानक उसकी तबियत बिगड़ गई और वह नीचे बैठ गया। जैसे ही मेडिकल टीम को इसकी सूचना मिली मेडिकल की टीम मौके पर पहुंची और उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। फिर उसे मौजूद चिकित्सकों की टीम ने मेडिकल अस्पताल भेज दिया। वन विभाग की टीम द्वारा तत्काल सुख सिंह को उपचार के लिए मेडिकल हॉस्पिटल लेकर पहुंची जहां चिकित्सकों ने सुख सिंह को मृत घोषित कर दिया। सुख सिंह की मौत कैसे और किन परिस्थिति में हुई है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

वन विभाग से कोरबा रेंजर मृत्युंजय शर्मा ने बताया की वनरक्षक की भर्ती के लिए अभिव्यक्ति के रूप में सुख सिंह आया हुआ था जहां 200 मीटर रनिंग पर करने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी इंस्टाग्राम मौजूद डॉक्टरों की टीम के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया जहां हालत बिगड़ने पर उसे जिला मेडिकल कॉलेज से लेकर पहुंचे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रमोद डनसेना ने बताया कि जिला मेडिकल कॉलेज से मिले में मेमो के आधार पर पंचनमा कार्यवाही कि जा रही है मृतक के परिजनों का बयान दर्ज किया जाएगा।

वन विभाग ने मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। आगे चिकित्सकों के टीम द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के वास्तविक के कारण का खुलासा हो पाएगा। मृतक सुख सिह जब छोटा था तब उसके पिता की मौत हो गई है चार भाई और तीन बहनों में सबसे छोटा था और बी ए फर्स्ट ईयर का छात्र पढ़ने लिखने में काफी होशियार था और सरकारी नौकरी करना उसका सपना था। मृतक भर्ती प्रक्रिया करने के लिए शुक्रवार की उरगा थाना अंतर्गत बरीडीह अपने रिश्तेदार के घर आ कर रुका हुआ था।

संक्षिप्त समाचार

चेम्बर कार्यकारिणी समिति की बैठक 17 को

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी,विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि चेम्बर कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन 17 दिसम्बर 2024 को दोपहर 12 बजे चेम्बर कार्यालय, चै. देवीलाल व्यापार उद्योग भवन, बाम्बे मार्केट, रायपुर में आयोजित है। चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर पारवानी ने प्रदेश के समस्त कार्यकारिणी सदस्यों से अपील की है कि वे बैठक में समय पर अवश्य ही उपस्थित होवें।

सोल्जीराथन आज, ऐतिहासिक विजय उत्सव मनाने होंगी कई स्पर्धायें

रायपुर। नवा रायपुर में 15 दिसम्बर को सोल्जीराथन का आयोजन किया गया है। इसमें 1971 के युद्ध में देश की ऐतिहासिक विजय का उत्सव मनाने के लिए विविध स्पर्धाएं आयोजित की जायेगी। इस युद्ध में देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले वीरगति को प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में दौड़ और पैदल चाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की दौड़ शामिल है। यह दौड़ नवा रायपुर स्थित सेंट्रल पार्क से शुरू होगी। आयोजन में प्रतिभागियों और दर्शकों की सुविधा के लिए 15 दिसंबर को सुबह 5 बजे से रायपुर के विभिन्न स्थानों से नवा रायपुर तक विशेष बीआरटीएस बस सेवा निशुल्क उपलब्ध होगी। ये बसें प्रमुख स्थानों जैसे भाटागांव बस स्टैंड, पंचपेड़ी नाका, कमल विहार, देवपुरी चौक, अटल एक्सप्रेस मार्ग और रेलवे स्टेशन से चलेंगी। सोल्जीराथन का मुख्य उद्देश्य 1971 के युद्ध में वीर सैनिकों के योगदान को स्मरण करना और समाज में उनके प्रति सम्मान की भावना जागृत करना है। आयोजक समिति ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और इसे सफल बनाएं।

छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल महिला संगठन रायपुर जिला इकाई की अध्यक्ष बनी प्रियंका

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल महिला संगठन रायपुर जिला इकाई की प्रथम बैठक संरक्षिका अनिता अग्रवाल एवं प्रांतीय अध्यक्षा गंगा अग्रवाल के नेतृत्व में सम्पन्न हुई। जिसमें नवनियुक्त रायपुर जिले की अध्यक्षा प्रियंका अग्रवाल ने अपनी टीम का गठन करते हुए सचिव की जिम्मेदारी सारिका खेतान, कोषाध्यक्ष संतोष धनोदीया, मीडिया प्रभारी ज्योति अग्रवाल के अलावा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की। इस दौरान प्रियंका ने की टीम ने बढ़ते ठंड को देखते हुए निर्णय लिया कि गरीब बच्चों को जल्द से जल्द स्वेटर व मोजा का वितरण किया जाएगा और इसकी शुरुआत वे रामसागर पारा स्थित आवासीय बाल आश्रम से करने जा रहे है। मीडिया प्रभारी ज्योति अग्रवाल ने बताया ईकाई की प्रथम बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा की गई। जिसके तहत रविवार को उनकी टीम सबसे पहले भगवान श्रीराम के दर्शन करने के लिए अयोध्या रवाना होने वाली है। वहां से लौटने के बाद बढ़ते ठंड को देखते हुए रामसागर पारा स्थित आवासीय बाल आश्रम में करीब 100 बच्चों को स्वेटर एवं मोजा का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा उनकी टीम के द्वारा जरुरतमंदों को भी स्वेटर व कंबल का वितरण किया जाएगा ताकि वे इस ठंड से अपने आप को सुरक्षित रख सकें।

खुशहाल एक साल इवेंट रविवार को मैग्नेटो मॉल में शाम 4 बजे से

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर शासन की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति नागरिकों को जागरूक करने जनसंपर्क विभाग द्वारा मैग्नेटो मॉल रायपुर में 15 दिसंबर रविवार को खुशहाल एक साल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है । यह कार्यक्रम शाम 4 बजे से 7 बजे तक होगा जिसमें विभिन्न तरह की मनोरंजक गतिविधियों और गेम्स का आयोजन भी होगा । इसमें प्रत्येक आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं । कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में पूछे गए रोचक प्रश्नों का सही उत्तर देने पर तत्काल गिफ्ट वाउचर मौक़े पर ही दिया जाएगा।

रविवार से खरमास, माह पर नहीं होंगे मांगलिक कार्य

रायपुर। आज रविवार से खरमास प्रारंभ हो जायेगा इसलिए अब माह पर शुभ मांगलिक कार्यों पर विराम लग जायेगा। धर्म संवत बताया गया है कि शुभ विवाह व मांगलिक कार्य एक माह तक नहीं होंगे, क्योंकि 15 दिसंबर रविवार से खरमास शुरू हो रहा है। इसमें शुभ कार्य नहीं होते हैं। पंडितो ने बताया कि पंचांग की गणना के अनुसार 15 दिसंबर से एक माह तक शादी-विवाह सहित सभी मंगल कार्य नहीं होंगे। 16 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में मार्गी होंगे।16 जनवरी से विवाह के शुभ मुहूर्त सहित अन्य मंगल कार्य शुरू होंगे। बताया जाता है कि जब सूर्य धनु राशि में रहता है, उस समय को खरमास कहते हैं। खरमास में शादी-विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश आदि जैसे शुभ कार्य नहीं होते हैं। 15 दिसंबर से खरमास लग रहा है। इस दिन सूर्य रात 10.19 बजे धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 30 दिनों तक यानी 15 जनवरी तक इसी राशि में रहेंगे। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब खरमास खत्म हो जाएगा। मान्यता है कि इस समय किए जाने वाले कार्यों में स्थायित्व में कमी मानी जाती है।

साय के नेतृत्व में हर वर्ग के लिए हुआ कार्य, निभाया वादा : मूणत

बालोद में गिनाई छत्तीसगढ़ सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियाँ

बालोद। छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और रायपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक, श्री राजेश मूणत ने शनिवार को प्रदेश में भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नेतृत्व में हुए कार्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। राजेश मूणत ने कहा, 13 दिसंबर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा हो गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कई नए आयाम स्थापित किए गए हैं।

हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर काम किया है, खासकर उन लोगों के लिए जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं।उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता का घोर अभाव था, जबकि भाजपा सरकार ने इन दोनों मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। हमने सुशासन स्थापित करने का जो वादा किया था, उसे निभाया और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं।

मुख्य उपलब्धियाँ-

1. किसानों के लिए रिकॉर्ड समर्थन मूल्य-सरकार ने किसानों से किए गए वादे के अनुसार 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की रिकॉर्ड खरीदी की है और 3716 करोड़ रुपए का बकाया दान पुन भुगतान भी किया है। 2. महतारी वंदन योजना-इस योजना के तहत 70 लाख माता बहनों को लाभ मिल रहा है, जिसमें अब तक 6530 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। 3. आवास योजना- 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण प्रारंभ किया गया, जिसमें सरकार ने बड़े पैमाने पर राशि जारी की है। 4. गरीबों के लिए राशन- सरकार ने प्रदेश के 68 लाख गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की है। 5. लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन: लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन को बहाल करने के साथ-साथ 5 वर्षों का एरियाज भुगतान भी किया गया है।

जनजाति समाज के लिए कदम

प्रदेश में जनजाति समाज के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जनजाति समाज के गौरव को बढ़ाने के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण दर को रू. 4000 से बढ़ाकर रू. 5500 मानक पूरा किया गया। इसके अलावा, जनजाति क्षेत्र में सड़क, रेल और हवाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अंबिकापुर से हवाई सेवा की शुरुआत एक बड़ी उपलब्धि है।

पर्यटन के क्षेत्र में विकास

छत्तीसगढ़ के पर्यटन क्षेत्र में विकास की दिशा में किए गए प्रयासों को भी साझा किया। बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर के निर्माण से राज्य में पर्यटन के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। कानगिर घाटी के गांव धुड़मारस को संयुक्त राष्ट विश्व पर्यटन संगठन द्वारा दुनिया के चुनिंदा 20 पर्यटन गांवों में शामिल किया गया है।

नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई

मूणत ने नक्सलवाद के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में 213 नक्सलियों को मार गिराया गया और लगभग 1750 नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने या गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।` बस्तर के अंदरूनी गांवों तक लोकतंत्र और विकास की पहुँच बनाने के लिए योजनाएँ बनाई हैं.

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ स्थलों की यात्रा को बढ़ावा देने की बात भी की। इसके साथ ही राज्य में पांच शक्तिपीठों के विकास और श्री राम लाल दर्शन योजना की शुरुआत का भी उल्लेख किया, जो छत्तीसगढ़ को भगवान राम के इतिहास से जोडने् के उद्देश्य से शुरू की गई है।

सरकार का पहला वर्ष छत्तीसगढ़ के विकास और कल्याण के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। उनकी सरकार ने सभी वर्गों की जरूरतों को प्राथमिकता दी है और आने वाले वर्षों में भी यही संकल्प लेकर काम करेगी।

छत्तीसगढ़ राज्य तैयार कर रहा है ईको-रेस्टोरेशन पॉलिसी

■ **केरल के बाद देश का दूसरा राज्य होगा छत्तीसगढ़**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शदन में छत्तीसगढ़ राज्य में ईको-रेस्टोरेशन पॉलिसी तैयार की जा रही है। केरल के बाद, यह छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जो यह पॉलिसी तैयार कर रहा है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में राज्य को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।

भारत की ग्लोबल रेस्टोरेशन इनिशिएटिव, बॉन चैलेंज और संयुक्त राष्ट ईको-रेस्टोरेशन दशक में भागीदारी यह स्पष्ट करती है कि एक केंद्रित ईको-रेस्टोरेशन नीति अनिवार्य है। पारंपरिक वनीकरण, जो प्राय- अत्यधिक लागत वाला होता है और गैर-स्थानीय प्रजातियों पर आधारित होता है, सीमित पारिस्थितिक लाभ प्रदान करता है। इसे ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में अपने निर्देश के तहत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसने ईको-रेस्टोरेशन को प्राथमिकता देने की सिफारिश की। जैव विविधता के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए ईको-रेस्टोरेशन अत्यंत आवश्यक है। यह पहल एक अधिक समावेशी और सुदृढ़ पर्यावरणीय भविष्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री व्ही. श्रीनिवास राव ने बताया कि ईको-रेस्टोरेशन पॉलिसी का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के खोए हुए वन क्षेत्रों, आर्द्रभूमियों और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों को पुनर्स्थापित करना है। नीति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, हितधारकों एवं समाज के सभी वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इस पॉलिसी का अंतिम मसौदा जनवरी माह में राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज के तत्वाधान में दो राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है। कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ को पारिस्थितिक पुनर्स्थापना के क्षेत्र में एक व्यापक और प्रभावशाली नीति बनाने में सक्षम बनाना है, जो अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बनेगी।

डबल इंजन की सरकार में रेल नेटवर्क को मिल रही मजबूती

बस्तर और सरगुजा के सुदूर वनांचलों में भी बिछ रही नई रेल लाइनें

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की डबल इंजन की सरकार में रेल नेटवर्क का लगातार विस्तार हो रहा है। यहां नई रेल लाइन बिछाने की कई परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मजबूत हो रहे रेल नेटवर्क से आने वाले समय में न केवल माल परिवहन की सुविधाओं में इजाफा होगा, बल्कि यहां के लोगों को राज्य के भीतर और राज्य के बाहर भी सुविधाजनक यात्रा के कई नए विकल्प मिलेंगे। राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार से औद्योगिक और अधोसंरचना विकास को भी नई गति मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार और रेल मंत्रालय के बेहतर समन्वय से राज्य में नई रेल लाइनों के काम द्रुत गति से चल रहे हैं। रावघाट रेलवे लाइन परियोजना के अंतर्गत दल्लीराजहरा से अंतागढ़ तक नई बिछी 77 किलोमीटर लाइन पर यात्री ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इस रेल लाइन के दोनों ओर बसे हजारों ग्रामीण अब अपने गांव से ही ट्रेन में बैठकर रोज दल्लीराजहरा, दुर्ग, भिलाई और रायपुर तक किफायती सफर कर रहे हैं। इस रेल लाइन को रावघाट तक बढ़ाने के लिए तुमापाल (ताहोकी) से कोसरोण्डा तक पांच पुल-पुलियों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। रेल पटरी बिछाने का कार्य भी प्रगति पर है। कोसरोण्डा से फुलपाड़ एवं फुलपाड़ से रावघाट तक अर्थ वर्क के साथ 21 पुल-पुलियों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। साथ ही 27 पुल-पुलियों का काम प्रगति पर है। सरगीपाल के पास रेलवे स्टेशन के भवन, प्लेटफॉर्म और आवासीय भवन का कार्य भी प्रगति पर है। रावघाट के भिलाई से रेल मार्ग से जुड़ जाने से भिलाई इस्पात संयंत्र को बड़े पैमाने पर लौह अयस्क की आपूर्ति हो सकेगी। साथ ही इस सुदूर क्षेत्र के लोगों को यातायात का एक सर्वसुलभ और किफायती साधन भी उपलब्ध होगा।

बस्तर में के.के. (कोत्तावलसा से किरंदुल) रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना का काम भी तेजी से चल रहा है। इस 446 किलोमीटर लंबे रेल लाइन का 170 किलोमीटर हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। बस्तर जिले में इसकी लंबाई 92 किलोमीटर और दंतेवाड़ा जिले में 78 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में इस रेल लाइन के 148 किलोमीटर में दोहरीकरण का काम पूर्ण हो गया है, जिनमें बस्तर जिले में आने वाला 92 किलोमीटर और दंतेवाड़ा जिले का 56 किलोमीटर रेल लाइन शामिल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय प्रदेश की आर्थिक तरक्की के लिए रेल परिवहन के समुचित उपयोग पर जोर दे रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग से राज्य में कई रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहे हैं। साथ ही कई परियोजनाओं के विस्तार की तैयारी है। 295 किलोमीटर लंबी और 4021 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली डोंगरगढ़-कवर्धा-कटघोरा रेल लाइन परियोजना की मंजूरी रेल मंत्रालय से मिल चुकी है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक निर्माण कार्यों के लिए अभी 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस रेल लाइन में डोंगरगढ़ से कवर्धा के बीच 12 और कवर्धा से कटघोरा के बीच 15 स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में न केवल यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, बल्कि खनिजों के परिवहन और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।

राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने कई नई रेल परियोजनाओं पर काम हो रहे हैं। 180 किलोमीटर लंबी कोरबा-अंबिकापुर नई रेल लाइन के सर्वेक्षण और डीपीआर के लिए 16 करोड़ 75 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना से सरगुजा क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। गढ़चिरौली-बीजापुर-बचेली तक 490 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के सर्वेक्षण के लिए भी सवा 12 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना से सुदूर क्षेत्रों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से जोडने् में मदद मिलेगी।

सरडेगा-भालुमुडा के बीच 37 किलोमीटर डबल लाइन परियोजना ओड़िशा और छत्तीसगढ़ के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करेगी। इसके लिए 1360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में अम्बिकापुर-बरवाडीह, खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा, रावघाट-जगदलपुर और धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा रेल परियोजनाओं का भी डीपीआर तैयार हो रहा है।

शीतलहर को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट

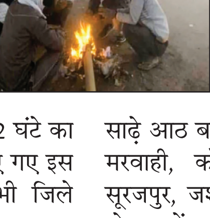

रायपुर। रायपुर सहित दूसरे जिलों में सर्दी और कड़ाके की ठंड पिछले एक सप्ताह से पड़ रही है। न्यूनतम तापमान में भी 5 से 7 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। जिसके कारण ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए शीत लहर चलने को लेकर 24 से 72 घंटे का येलो अलर्ट भी जारी किया है। जारी किए गए इस येलो अलर्ट में सरगुजा संभाग के सभी जिले शामिल हैं।

24 घंटे के लिए 15 दिसंबर की सुबह साढ़े आठ बजे तक प्रदेश के गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा, मुंगेली, दुर्ग, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कबीरधाम, जशपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर के एक दो स्थानों पर शीत लहर चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।

48 घंटे के लिए 16 दिसंबर की सुबह साढ़े आठ बजे तक के लिए प्रदेश के गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, दुर्ग, कोरबा, खैरागढ़, छुईखदान गंडई, कबीरधाम, जशपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर के एक दो स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है। 17 दिसंबर की सुबह साढ़े आठ बजे तक के लिए प्रदेश के गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरिया, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, सूरजपुर, जशपुर सरगुजा और बलरामपुर के एक दो स्थानों पर शीत लहर चलने की संभावना है।

प्रदेश के जिलों में यदि शनिवार के तापमान की बात की जाए तो कोरिया में 7.4 डिग्री, सूरजपुर में 7.8 डिग्री, बलरामपुर में 4.8 डिग्री, सरगुजा में 5.9 डिग्री, जशपुर में 10.7 डिग्री, कोरबा में 10.2 डिग्री, गौरेला पेंड्रा मरवाही में 8 डिग्री, बिलासपुर में 12.6 डिग्री, रायपुर में 13.4 डिग्री, दुर्ग में 9.2 डिग्री, राजनादगांव में 11.2 डिग्री, बस्तर में 13.8 डिग्री, बीजापुर में 13.9 डिग्री, दंतेवाड़ा में 12.6 डिग्री दर्ज किया गया।

रायपुर में विस्फोट, पति ने लगाई आग

जान बचाने पड़ोसी के घर घुसी पत्नी, एक की मौत, पांच झुलसे

रायपुर। रायपुर से आगजनी की बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के भनपुरी के रामेश्वर नगर में पति और पत्नी के बीच हुए विवाद एक की मौत और पांच लोग गंभीर रुप से झुलस गये हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस आगजनी के दौरान पुलिस महिला को घर से बाहर निकाल ही रही थी, तभी सिलेंडर फट गया। इसे दो आरक्षक समेत पांच लोग झुलस गए। हादसे में पति की गंभीर रुप से जलने से उसकी मौत हो गई है। घटना बीती रात साढ़े दस बजे की है।

बताया जाता है कि घरेलू विवाद पर में बी अमरेश्वर राव उर्फ राजा ने अपनी पत्नी के संध्या रानी पर चाकू से जानलेवा हमला किया। संध्या किसी तरह जान बचाकर घर से भागकर पड़ोसी के घर में घुसी। इसके बाद पति राजा ने मकान के भीतर आग लगा दी। घटना खमतराई थाने क्षेत्र की है। पुलिस के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच हुए विवाद में सूचना पर पुलिस पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान पति ने घर में आग लगा ली। पुलिस महिला को जैसे ही घर से बाहर निकाल रही थी, तभी सिलेंडर फट गया। इस हादसे में पेट्रोलिंग टीम के दो आरक्षक विकास सिंह और हेमंत गिलहरे झुलस गए। इसके साथ ही तीन अन्य नागरिक भी झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। वहीं 40 वर्षीय पति राजा राव की आग में जलने से मौत हो गई।

आगजनी की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। दमकल टीम ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घर के अंदर घुसकर मृत पति का शव बाहर निकाला। पुलिस मामला दर्ज कर घटना की जांच कर रही है।

राइस मिलर्स हड़ताल : पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र

रायपुर। पूर्व विधायक ननकीराम कंवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल को पत्र लिख कर राइस मिलरों के बकाया का जिक्र करते हुए भुगतान की बात कही है। उन्होंने समितियों में जमा धान के उठाव के लिए शासन और राइस मिलरों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की मांग की है, जिससे किसानों में पनप रहे आक्रोश का असर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में देखने को न मिले।

पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने अपने पत्र में लिखा कि राइस मिलर को प्रदेश सरकार की उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। इन्हें अपने कार्य का पैसा दो-तीन साल से नहीं मिलने की बात कहते हुए इससे इतनी बड़ी इण्डस्ट्री को चलाने में आने वाली दिक्कत से अवगत कराया।

इसके साथ ही पूर्व मंत्री ने पूर्व में शासन द्वारा स्थापित की गई खुद की किसान राइस मिल के प्रशासन की गलत नीति से बंद हो गई। अब वही गलत नीति शासन द्वारा राइस मिलरो के साथ अपनाई जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि राइस मिलों को बंद कराकर शासन अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के धान को खरीदने की इच्छुक नहीं है।

कंवर ने बिगड़ती स्थिति पर प्रधानमंत्री से स्वंय के संज्ञान में लेने का आग्रह करते हुए अपेक्षा है कि आप इस बिगड़ती व्यवस्था को स्वयं से संज्ञान में आग्रह किया है। अपने आप को जमीन से जुड़ा हुए बताते हुए कहा कि आज जनता अपने धान का उठाव नही होने से अपना धान समिति में नहीं बेच पा रही है, जिससे किसानों में सरकार के प्रति अत्यधिक आक्रोश उत्पन हो रहा है, जिसका परिणाम हमें वर्तमान निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनाव में देखा जा सकता है।

बहाल हुई दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस

■ **रेलवे ने वापस लिया निर्णय, 17 से नियमित चलेगी**

रायपुर। रेल यात्रियों के लिये खुशखबरी है। महाकुंभ के लिये प्रयागराज जाने वाले रेल यात्रियों की मांग को देखते हुए रद्द की गई सारनाथ एक्सप्रेस दोबारा बहाल कर दी गई है।

दुर्ग-छपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस को 2 दिसम्बर 2024 से 27 फरवरी 2025 के बीच कोहरे की अग्रिम आशंका के कारण कुछ तिथियों में रद्द किया गया था। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जाने वाले रेल यात्रियों की मांग को ध्यान रखते हुये रेल प्रशासन ने रद्द की गई सारनाथ एक्सप्रेस को 17 दिसम्बर 2024 से दोबारा नियमित परिचालन शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान ट्रेन में होने वाली अतिरिक्त भीड़ के नियंत्रण के लिये रेल यात्रियों को अधिक से अधिक कन्फर्म बर्थ/सीट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से तीन कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो रायगढ़, बिलासपुर एवं दुर्ग स्टेशनों से चलेंगी।

रेलवे ने यात्रियों की बेहतर सुविधा को देखते हुए कंफ़र्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से बिलासपुर एवं एलटीटी के मध्य क्रिसमस फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी जा रही है। गाड़ी संख्या 08293/08294 बिलासपुर-एलटीटी-बिलासपुर स्पेशल ट्रेन एक फेरे के लिए बिलासपुर से 24 दिसंबर, 2024 को एवं एलटीटी से 25 दिसंबर 2024 को चलाई जायेगी । इस स्पेशल ट्रेन में इस स्पेशल ट्रेन में 2 एसएलआरडी, 4 सामान्य, 10 स्लीपर, 02एसी टू टीयर, 2 एसी थ्री टीयर सहित कुल 20 कोच के साथ चलेगी।

इस गाड़ी में रेलवे ने स्पेशल ट्रेन में एक एसी-3 कोच एवं दो स्लीपर सहित तीन अतिरिक्त् कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । यह सुविधा गाड़ी संख्या 08293 बिलासपुर-एलटीटी स्पेशल में दिनांक 24 दिसंबर 2024 को तथा गाड़ी संख्या 08294 एलटीटी-बिलासपुर स्पेशल में दिनांक 25 दिसंबर 2024 को उपलब्ध रहेगी । इस सुविधा की उपलब्धता से इस गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्री लाभान्वित होंगे ।

संसद में गतिरोध असली मुद्दों से भटकाव है

राशिद किदवई

संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में अब तक जो कुछ देखा गया, वह निराशाजनक है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर रार के अलावा अगर अब तक की संसद में चली कार्यवाही को देखें, तो इससे बहुत शुभ संकेत नहीं मिलते हैं। विगत 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, लेकिन इसमें अभी तक शायद ही जनहित के किसी मुद्दे पर कोई सार्थक चर्चा हुई है। शीतकालीन सत्र के लिए जो एजेंडा तय किया गया था, उस पर भी न के बराबर काम हुआ है। आलम यह है कि संसद के दोनों सदन हर रोज बगैर किसी विशेष कामकाज के स्थगित किये जा रहे हैं। संसद का काम देश के लिए कानून बनाना तो है ही, साथ ही साथ देश और विदेश के जो महत्वपूर्ण मसले हैं, उन पर चर्चा करना भी है। इन चर्चाओं के लिए संसद से अच्छा और बड़ा फोरम और कोई हो ही नहीं सकता। इस देश में कई समस्याएं हैं। मणिपुर का मसला है। 'वन नेशन- वन इलेक्शन' का मुद्दा है, जिस पर खुद सरकार भी चर्चा चाहती है। इसके अलावा भी वक्फ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट जैसे कई मुद्दे हैं। भारत से इतर दुनिया में भी कई घटनाएं हो रही हैं। जैसे सीरिया का मसला है। सब जानते हैं कि इसके कई दीर्घकालीन परिणाम होंगे। इस मुद्दे पर पूरे सदन में चर्चा होनी चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उसकी प्रतिक्रियाएं देश की सड़कों पर तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े मंच से यह मुद्दा सिरे से नदारद है। संसद वह फोरम है, जहां यह बताना सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अहम मसलों पर क्या कर रही है। दूसरी तरफ सकारात्मक विरोध करना या सुझाव देना विपक्ष का कर्तव्य है। दुर्भाग्य से सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ही संसद की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं या जानबूझकर उसकी अवहेलना कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों से कई वरिष्ठ सांसद हैं। कुछ सांसद तो सात-सात, आठ-आठ बार चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे हैं। लेकिन वे भी बीच का कोई रास्ता नहीं सुझा पा रहे हैं। संसद में गतिरोध कोई नयी बात नहीं है। पहले भी कई बार गतिरोध की स्थिति आयी है। लेकिन तब लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति इस तरह के गतिरोधों को तोड़ने की पहल करते थे। परंतु अब समस्या यह है कि विपक्ष उन्हें सत्ता पक्ष का ही एक अंग मानकर बर्ताव कर रहा है। इससे लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, दोनों के संवैधानिक अधिकारों तथा कर्तव्यों पर भी बड़ा सवाल उठता है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को तो भारतीय संसद के इतिहास में अभूतपूर्व ही कहा जा सकता है। इस प्रस्ताव का मतलब है देश के उपराष्ट्रपति के प्रति अविश्वास जताना, जो राष्ट्रपति के बाद देश में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। जगदीप धनखड़ से पहले इस देश में 13 उपराष्ट्रपति हो चुके हैं, लेकिन प्रथम उपराष्ट्रपति डॉ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर हामिद अंसारी तक ने बतौर सभापति राज्यसभा का संचालन करते हुए न केवल निष्पक्षता बरती, बल्कि वे निष्पक्ष नजर भी आये। यहां तक कि जगदीप धनखड़ से पहले उपराष्ट्रपति रहे एम वेंकैया नायडू ने भी राज्यसभा के संचालन में कमोबेश निष्पक्षता बरती थी। यहां यह याद दिलाया जाना आवश्यक है कि के आर नारायणन और उनसे पहले तक के तमाम उपराष्ट्रपति तो प्रश्नकाल के बाद राज्यसभा की कार्यवाही से दूर हो जाते थे और सदन चलाने का जिम्मा उपसभापति के हवाले कर दिया जाता था। ऐसा इसलिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि राज्यसभा में होने वाली तीखी राजनीतिक बहस के दौरान एक उपराष्ट्रपति का सभापति की कुर्सी पर बैठे रहना नैतिक तौर पर उचित नहीं रहेगा। विपक्ष का यह अविश्वास प्रस्ताव अगर अभूतपूर्व है, तो इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से आयी प्रतिक्रिया भी वैसी ही है। भाजपा सांसद संबित पात्रा द्वारा उपराष्ट्रपति का बचाव यह कहकर किया गया है कि वह एक समुदाय विशेष से आते हैं, और अविश्वास प्रस्ताव का यह नोटिस केवल उस राष्ट्रभक्त समुदाय का अपमान करने के लिए दिया जा रहा है। यह भी संभवत¬ पहली ही बार हो रहा है कि संवैधानिक पद के साथ जाति को इस तरह नत्थी किया जा रहा है, और इसके बहाने विपक्ष को प्रकारांतर से राष्ट्र विरोधी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष जिस तरह से अडानी के मुद्दे को लेकर अटका हुआ है, उससे आम जनता में यह संदेश जा रहा है कि उसके पास क्या इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है?

ग्रेटर इजरायल प्लान क्या है?

कमलेश पांडे

क्या आपको पता है कि 19वीं सदी में यहूदीवाद (जायोनिज्म) आंदोलन की आधारशिला रखने वाले थियोडोर हर्जेल ने एक ऐसे यहूदी देश की अवधारणा रखी थी, जो अरब के एक बड़े इलाके में फैला हुआ होगा। यदि नहीं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि यहूदीवाद, यहूदियों का तथा यहूदी संस्कृति का राष्ट्रवादी राजनैतिक आन्दोलन है जो इसराइल के ऐतिहासिक भूभाग में यहूदी देश की पुनर्स्थापना का समर्थन करता है।

दरअसल, जायोनिज्म का आरम्भ मध्य एवं पूर्वी यूरोप में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। यह यूरोप के सिमेटिक विरोधी राष्ट्रवादी आन्दोलनों के प्रतिक्रियास्वरूप एक राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन आन्दोलन के रूप में शुरू हुआ। यहूदीवाद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है कि फिलिस्तीन में यहूदीकरण तथा यहूदीबाद का विस्तार करना, जिसके लिए इसकी विश्व में बहुत आलोचना हो चुकी है। हालांकि इसके शीघ्र बाद इस आन्दोलन के अधिकांश नेताओं ने फिलिस्तीन के अन्दर अपना देश बनाने का लक्ष्य स्वीकार किया। फिलिस्तीन उस समय उसमानी साम्राज्य के अधीन था।

यही वजह है कि समय-समय पर इजरायल में इसे लेकर चर्चाएं होती रही हैं। बहरहाल सारिया में रूस समर्थित बशर अल-असद की क्रूर सत्ता के पतन के बाद अब एक बार फिर से इसकी चर्चा तेज हो गई है। क्योंकि तुर्की के साठगांठ और अमेरिका-इजरायल के परोक्ष सहमति से सीरिया में बशर अल-असद के पतन की पृष्ठभूमि तैयार की गई और इस दु:स्वप्न के साकार होने के बाद ही एक बार फिर से %ग्रेटर इजरायल% की चर्चा तेज हो गई। क्योंकि बिना कोई समय गंवाए इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आदेश के बाद इजरायली सेना ने अल्फा लाइन को पार कर लिया और सीरिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया।

इसके अलावा, इजरायल और अमेरिका की संयुक्त बमबारी करके सीरिया में सफल हुए विद्रोहियों की सेना को कमजोर कर दिया गया। उसकी थल, जल और वायु मारक क्षमता वाले हथियारों को लगातार नेस्तनाबूद किया गया। समझा जाता है कि ग्रेटर इजरायल में कई अरब देशों के हिस्से इजरायल के नेतृत्व वाले यहूदी देश में शामिल होंगे। क्योंकि ग्रेटर इजरायल प्लान में अरब का एक बड़ा इलाका शामिल है, जिसे साकार करने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।

कारण कि सीरिया में बशर अल असद की सत्ता मिटने से ईरान ज्यादा कमजोर हुआ है। वहीं, रूस के पांव ही अरब मुल्क से उखड़ चुके हैं, जिससे अफ्रीका तक में रूसी रणनीति अब प्रभावित होगी। इससे एक ओर जहां अमेरिका-इजरायल की बल्ले-बल्ले हैं, वहीं तुर्की के एरदोगन भी अरब के मुस्लिम खलीफा बनने को ततपर नजर आ रहे हैं।

बता दें कि सीरिया में बशर अल-असद के शासन के लगभग ढाई दशक के शासन के खत्म होते ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सेना को गोलान हाइट्स पर इजरायली कब्जे के पार सीरियाई क्षेत्र में जाने का आदेश दिया और इजरायली सेना ने टैंकों के साथ सीमा को बांटने वाली अल्फा लाइन को पार कर लिया। लिहाजा, इजरायली सेना के इस कदम के बाद से ही ग्रेटर इजरायल की परिकल्पना को साकार करने को लेकर चर्चाएं पुन: तेज हो गई हैं।

यह बात मैं नहीं कह रहा बल्कि खुद को मानवाधिकार कार्यकर्ता और इतिहासकार बताने वाले क्रेग मरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ग्रेटर इजरायल को लेकर एक बड़ा दावा किया है, जिससे अरब देशों में सनसनी मच गई है। दरअसल, उन्होंने कहा कि, सीरिया में एक नई सरकार आकार ले रही है, जिसकी फंडिंग और तैयारी तुर्की, अमेरिका, इजरायल और खाड़ी देश कर रहे हैं।% यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि %यह लोकतंत्र का सांठगांठ मानवाधिकारों के बारे में नहीं है। बल्कि यह ग्रेटर इजरायल और फिलिस्तीनियों के नरसंहार के बारे में है।

इसलिए अब सवाल उठता है कि आखिर ग्रेटर इजरायल का अभिप्राय क्या है ? तो एक बार फिर यहां स्पष्ट कर दें कि ग्रेटर इजरायल का मतलब उस बड़े अरब भूभाग से है, जहां तक कभी प्राचीन यहूदी राज्य हुआ करता था। इसे मध्य पूर्व के लिए जायोनिस्ट (यहूदीवादी) विस्तारवादी योजना भी कहा जाता है। जानकार बताते हैं कि 19वीं सदी में यहूदीवाद की स्थापना करने वाले थियोडोर हर्जेल ने इसकी अवधारणा दी थी। इसमें मिस्र की नील नदी से यूफ्रेट्स और मदीना से लेकर लेबनान तक का इलाका शामिल है। यानी इस क्षेत्र में मिस्र, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, पूरा जॉर्डन और कब्जे वाला फिलिस्तीनी क्षेत्र शामिल है।

समझा जाता है कि इस विशाल इलाके में अमेरिकी प्रभुत्व होने के कारण इजरायल को यह स्वप्न साकार करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि इस स्वप्न के साकार होते ही उसकी सैन्य ताकत और क्षेत्रीय रणनीतिक प्रभुत्व क्षमता में और भी इजाफा हो जाएगा। समझा जाता है कि भारत का भी मूक समर्थन पुराने और भरोसेमंद दोस्त इजरायल को हासिल है, अन्यथा रूस को सीरिया से खदेड़ने का षड्यंत्र वह नहीं रचता और न ही उसमें शामिल होता। उधर, अमेरिका भी इस मुद्दे पर खामोशी के लिए भारत का अहसानमंद है।

वहीं, अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि बंगलादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो इस्लामिक षड्यंत्र चल रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में अखंड भारत यानी ग्रेटर इंडिया के सपने को साकार करने का आरएसएस का दबाव मोदी सरकार पर बढ़ रहा है। यह तभी संभव होगा, जब अरब देश कमजोर होंगे। चूंकि इजरायल की मजबूती ही अरब देशों की कमजोरी है। इसलिए ईरान से लेकर सीरिया तक में चीनी-रूसी दिलचस्पी के बाद भी भारत ने रणनीतिक तटस्थता बरती, जिससे अमरीकी-इजरायल गेम प्लान तो सफल हुआ ही, भारत के शत्रु व पाकिस्तान के समर्थक देश तुर्किये की करीबी भी रूस से घटी, जो भारत के लिए एक शुभ संकेत है।

सीआईए और रॉ से जुड़े लोग बताते हैं कि ग्रेटर इंडिया प्लान में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यामांर और ईरान के उन हिस्सों को भारत में शामिल करना है, जो कभी विशाल मगध साम्राज्य का हिस्सा रह चुके हैं। इसमें तिब्बत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव आदि स्वत: शामिल हो जाएंगे। इस क्षेत्र में न केवल सनातनी विचारों को मजबूत करना है, बल्कि हिंसा-प्रतिहिंसा के लिए कोई जगह न बचे, ऐसा प्रशासन मजबूत करना है। समझा जाता है कि चीन को काबू में रखने के लिए अमेरिका और मुसलमानों को कमजोर करने के लिए इजरायल भी ग्रेटर इंडिया प्लान से सहमत है, जो अभी सिर्फ कागजों पर है और नीतिगत रूप से खुफिया एजेंसी की प्राथमिकता में है।

अब सवाल है कि ग्रेटर इजरायल में क्या-क्या शामिल होगा? तो जवाब यही होगा कि इजरायली राजनीति में ग्रेटर इजरायल की बात कोई नई बात नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट मॉनिटर की एक रिपोर्ट भी इस बात की चुगली करती है, जिसके अनुसार, जनवरी 2024 को इजरायली राजनेता एवी लिपकिन ने कहा था कि, आखिरकार हमारी सीमाएं लेबनान से सऊदी अरब के ग्रेट डेजर्ट तक फैलेंगी। फिर भूमध्य सागर से फरात नदी (इराक) तक। और फरात के दूसरी तरफ कौन है? कुर्द! और वे हमारे दोस्त हैं। वहीं, लिपकिन ने आगे कहा कि, इसलिए हमारे पीछे भूमध्य सागर है और हमारे सामने कुर्द हैं, लेबनान है, जिसे वास्तव में इजरायल की छत्रछाया की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि फिर हम मक्का, मदीना और माउंट सिनाई पर कब्ज़ा करेंगे, और उन जगहों को शुद्ध करेंगे।

सीधा सवाल है कि क्या अमेरिका भी इस प्लान में शामिल है? तो जवाब स्वरूप कई इतिहासकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का भी कहना है कि यही वजह है कि इज़राइल धीरे-धीरे और रणनीतिक रूप से अपने पड़ोसियों, विशेष रूप से फिलिस्तीन से अधिक से अधिक भूमि हड़प रहा है। कई विश्लेषक यहां तक कहते हैं कि ग्रेटर इजरायल पूरी तरह से यहूदी प्लान नहीं है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका की सोच काम कर रही है, जिसका उद्येश्य मध्य पूर्व में अपने आधिपत्य का विस्तार करना है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले ब्रिटेन की एक योजना के चलते ही आगे चलकर इजरायली राज्य का गठन हुआ था, जिसे बाल्फोर घोषणा भी कहा जाता है। इसलिए अब अमेरिका-इजरायल की युगलबंदी में भारत की मौन वैचारिक व रणनीतिक छौंक क्या गुल खिलाएगी, जानना-समझना-इंतजार करना दिलचस्प रहेगा?

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

वेदों में एक स्थान में जिस वस्तु का विधान किया है अन्यत्र उसी का निषेध भी देखने में आता है यथा- (क) जतिलयवाग्वा वा जुहूयाद् गवीधुक्रयवाग्वा वा। (तैत्तिरीय 54 ।3 ।2)

(ख) अनाहुतिर्वै जतिलारच गवोधुकाश्च । (तैत्तिरीय 5 ।4 ।3)

अर्थात (क) जर्तिल-यवागू से अथवा गवीधुक-यवागू से हवन करना चाहिये। (ख) तिल और गवीधुक हवन योग्य नहीं हैं। यहाँ पहिले प्रमाण में जंगली तिल, माण्डमार भात और चौलाई को हवन के योग्य बताया गया है, हवन के अयोग्य कहा गया है। और दूसरे प्रमाण में इन्ही पदार्थों को तात्पर्य यह है कि शास्त्रों के इस प्रकार के परस्पर विरुद्ध जंचने वाले विधान अधिकारी भेद से सुव्यवस्थित होते हैं। जैसे अमुक यज्ञ-फल की इच्छा रखने वाले अधिकारी को जतिलादि का. हवन करना चाहिए और अमुक यज्ञ में अमुक फलाभिलाषी य मान को. न करना चाहिये। इसी प्रकार पद्म और लिङ्ग आदि पुराणों के परस्पर: विरुद्ध प्रतीत होने वाले विधानों की समस्या है। पद्म वैष्णव- सम्प्रदाय में दीक्षित होने वाले पुरुष के लिए शङ्ख-चक्र-धारण की विधि बताता है और लिङ्गपुराण शैवसम्प्रदायी पुरुष के लिए उनकी अनावश्यकता प्रकट करता है।

लोक में भी एक पुलिसमैन के लिये जिस प्रकार की वर्दी में रहना नितान्त आवश्यक है, सर्वसाधारण के लिये वैसी वेशभूषा धारण करना अपराध समझा जाता है। एक वृद्ध पुरुष अपने स्वस्थ पुत्र को अमृत बता कर घी खाने के लिये प्रेरित करता है, और वही वृद्ध उसी पुत्र के लिये उसकी रुग्णदशा में घी को न खाने का आदेश करता है। इत्यादि अनेक दृष्टान्तों के अनुसार परस्पर विरोधाभासों को आधिकारी भेद से सुव्यवस्थित किया जा सकता है।

क्रमशः ...

सरदार वल्लभभाई पटेल

ललित गर्ग

आज भारत के लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 74वीं पुण्यतिथि है। 15 दिसंबर, 1950 को मुंबई में उनका निधन हो गया था। वह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। हिन्दुस्तान को आजादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा सरदार पटेल ही भारतीय सिविल सेवा की निरंतरता को कायम रखने वाले निर्णायक व्यक्ति थे।

महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया। सरदार पटेल का स्मृति दिवस हमारे लिये प्रेरणा दिवस है। उनकी शिक्षाएं, जीवन-आदर्श एवं राष्ट्र को प्रदत्त अवदान हमें प्रेरणा देते रहेंगे। उनके विचार एवं सोच हमारे लिये जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने का आधार है। वे कहते थे कि अगर कोई चीज मुफ्त मिलती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है जबकि परिश्रम से पाई हुई चीज की कीमत ठीक तरीके से लगाई जाती है। लोगों को मेहनत और कर्म के लिए प्रेरित करते हुए वे कहा करते थे कि यह सच है कि पानी में तैरने वाले ही डूबते हैं, किनारे पर खड़े रहने वाले नहीं लेकिन इससे भी बड़ा सच यह है कि किनारे पर ही खड़े रहने वाले लोग तैरना भी नहीं सीखते।

अहिंसा का समर्थन करते हुए सरदार पटेल का कहना था कि कायरों की अहिंसा का कोई मूल्य नहीं है। जो तलवार चलाना जानते हुए भी तलवार को म्यान में रखता है, उसकी अहिंसा सच्ची अहिंसा होती है। वह कहते थे कि आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अपने मजबूत हाथों से अन्याय का डटकर सामना कीजिए। पटेल सदैव कहते थे कि गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। उनका कहना था कि हमारा सिर कभी न झुकने वाला होना चाहिए। हमें केवल भगवान के आगे झुकना चाहिए, दूसरों के आगे नहीं।

जीवन कैसे जीना चाहिए, इसका भी सरदार पटेल ने सम्पूर्ण दर्शन प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि जो कोई भी सुख और दुरूख का समान रूप से स्वागत करता है, वास्तव में वही सबसे अच्छी तरह से जीवन जीता है। हमें सदैव ईश्वर और सत्य में विश्वास रखकर प्रसन्न रहना चाहिए। यहां तक कि अगर हम हजारों की दौलत भी गंवा दें और हमारा जीवन बलिदान हो जाए तो भी हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। बहुत बोलने से कोई लाभ नहीं होता बल्कि हानि ही होती है। उन्हें देश के छोटे से छोटे स्तर के व्यक्ति की भी कितनी चिंता थी, उसी को व्यक्त करते हुए उन्होंने एकबार कहा था कि उनकी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई भी व्यक्ति अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा न रहे। सरदार पटेल का जीवन और दर्शन भातीयता को सुदृढ़ करने में नियोजित करने में लगा रहा है। एकता में सबसे बड़ा बाधक स्वहित है। आज के समय में स्वहित ही सर्वोपरि हो गया है। आज जब देश आजाद है, आत्मनिर्भर है तो वैचारिक मतभेद उसके विकास में बेड़ियाँ बनी हुई हैं। आजादी के पहले इस स्वार्थी दृष्टिकोण एवं स्वहित की भावना का फायदा अंग्रेज उठाते थे और आज देश के राजनीतिक लोग।

पाकिस्तान की सियासत में आईएसआई

मरिआना बाबर

इस हफ्ते बदलाव की बयार केवल सीरिया में ही नहीं बही, जहां एक राजवंश को जड़ से उखाड़ दिया गया, बल्कि न केवल पाकिस्तान में तेज हवाएं चलीं, अपितु?भूकंपीय बदलाव हुआ, जिसके दीर्घकालीन परिणाम तय हैं, क्योंकि इतिहास में पहली बार इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के एक पूर्व प्रमुख को राजनीतिक गतिविधियों के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए पाया गया। पूर्व खुफिया प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर एक सैन्य अदालत ने तीन मामलों में आरोप लगाया है-राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना, जासूसी विरोधी कानूनों का उल्लंघन करना और अपने पद का दुरुपयोग करना।

इस साल अगस्त में जब सेना ने फैज हमीद को गिरफ्तार करने की घोषणा की, तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ। इसका मतलब था कि मौजूदा सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर एक उदाहरण पेश कर रहे थे और सेना के दूसरे वरिष्ठ जनरलों को यह संदेश दे रहे थे कि अगर उन्होंने सेना के नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया, तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। अतीत में घरेलू राजनीति में आईएसआई के हस्तक्षेप की हमेशा आलोचना होती रही है, लेकिन यह पहली बार है कि आईएसआई के किसी पूर्व प्रमुख पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

फैज हमीद के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण आरोपों में से एक यह है कि नौ मई, 2023 की हिंसक घटनाओं में उनकी कथित भूमिका है, जिसमें भीड़ ने सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया और पूरे पाकिस्तान में सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर दिया। यह घटना तब हुई थी, जब इमरान खान को इस्लामाबाद की एक अदालत के परिसर से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले इमरान खान पर भी नौ मई के हिंसक

प्रदर्शन में उनकी कथित भूमिका के लिए आरोप लगे थे, जिसमें भीड़ ने रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय, लाहौर स्थित कोर कमांडर निवास और कई अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया था।

फिलहाल सैन्य हिरासत में रहने के दौरान पूर्व आईएसआई प्रमुख को सभी कानूनी अधिकार दिए गए हैं और उन्होंने अपने लिए एक बचाव वकील भी चुन लिया है, जो इसका संकेत है कि वह कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। दुर्भाग्य से, पूरी कानूनी लड़ाई बंद दरवाजों के पीछे होगी, क्योंकि सैन्य मामले सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि फैज हमीद अपने खिलाफ लगे आरोपों के बारे में सैन्य अदालत को क्या बताएंगे और वह इस मौके का इस्तेमाल खुद को निर्दोष साबित करने और दूसरों पर आरोप लगाने के लिए कैसे करेंगे।

फैज हमीद न केवल इतिहास में सबसे शक्तिशाली आईएसआई प्रमुख थे, बल्कि सबसे खतरनाक भी थे, जिन्हें बॉस होने के बावजूद किसी सेना प्रमुख द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, वह स्वतंत्र निर्णय लेते थे और विशेष रूप से घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करते थे। आम तौर पर, खुफिया प्रमुखों की पहचान गुप्त रखी जाती है और न तो कोई उन्हें पहचान पाता है और न ही उनके बारे में कोई मीडिया कवरेज होती है। लेकिन फैज हमीद को अपने काम से जुड़ी लोकप्रियता बहुत पसंद थी। यहां तक कि जब उन्हें देश के शीर्ष खुफिया अधिकारी का पद छोड़ने के लिए बाध्य किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें पेशावर में कोर कमांडर बनाकर स्थानांतरित कर दिया गया, तो उन्होंने काबुल के सेरेना होटल पहुंच कर अपनी तस्वीर खिंचवाई। उनकी वह तस्वीर दुनिया भर में वायरल हो गई, जिसमें वह ग्रीन टी की चुस्की लेते हुए मीडिया से कह रहे थे, 'सब ठीक हो जाएगा'।

यह कोई रहस्य नहीं था कि फैज हमीद काबुल में अफगान तालिबान से मिलने गए थे, क्योंकि वे भावी सरकार बना रहे थे। उस एक तस्वीर ने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान एक विदेशी सरकार के कामकाज में शामिल था, जो सत्ता में आ चुकी थी और कैबिनेट गठन की प्रक्रिया में जुटी थी। सेना छोड़ने के बाद भी फैज हमीद राजनेताओं के संपर्क में रहे और वह इतने अहंकारी और आत्मविश्वासी थे कि उन्होंने सेना की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान और उसी पार्टी के अन्य नेताओं से संपर्क बनाए रखा।

खबरें बताती हैं कि सेना से रिटायर होने के बाद फैज हमीद करीब 50 नेताओं के संपर्क में थे, जिनमें से ज्यादातर पीटीआई से थे। सेना जांच कर रही है कि क्या फैज हमीद का इमरान खान के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपर्क था, जब वह जेल में थे। संशोधित सेना अधिनियम के अनुसार, फैज हमीद को रिटायरमेंट की तारीख से पांच साल तक किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने से रोक दिया गया था।

जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, फैज हमीद आईएसआई प्रमुख थे और दोनों के बीच में नजदीकी बहुत बढ़ गई थी। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कबूल किया कि उन्होंने अपने आईएसआई प्रमुख का इस्तेमाल करके सांसदों को सत्ता पक्ष की इच्छा के अनुसार वोट देने के लिए मजबूर किया। सांसदों ने स्रोत का खुलासा किए बगैर कहा कि उन्हें कुछ शक्तिशाली लोगों से टेलीफोन कॉल आए थे और उन्होंने नेशनल असेंबली और सीनेट में सत्ता पक्ष के लिए वोट किया।

उस समय ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि इमरान खान ने जनरल कमर परवेज बाजवा की जगह फैज हमीद को नया सैन्य प्रमुख बनाने का वादा किया था। जब जनरल बाजवा को इस साजिश का पता चला, तो उन्होंने तुरंत फैज हमीद को पेशावर का कोर कमांडर बना दिया। इमरान खान और फैज हमीद, दोनों ने आईएसआई मुख्यालय से तबादले का विरोध किया, क्योंकि आईएसआई प्रमुख बहुत ताकतवर होता है। उस समय फैज हमीद के पास दो विकल्प थे, या तो वह इस्तीफा दे देते या पेशावर में कोर कमांडर का पद संभालते। अंतत: उन्होंने पेशावर जाना स्वीकार किया।

उसके तुरंत बाद इमरान खान को संसद में सदन के नेता पद से हटा दिया गया। यह पहली बार था, जब किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया। पीएमएल (एन) के शहबाज शरीफ और पीपीपी के आसिफ अली जरदारी के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टियों द्वारा लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव को तत्कालीन सैन्य प्रमुख जनरल बाजवा का पूरा समर्थन प्राप्त था। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर फैज हमीद के मुकदमे के दौरान यह साबित हो जाता है कि इमरान खान 9 मई को सेना के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल थे, तो क्या उन पर भी सैन्य अदालत में मुकदमा चलेगा?

आज का इतिहास

1950 कनाडा के कैलगरी शहर में भगदड़ खेत खेल स्टेडियम आधिकारिक तौर पर खोला गया।

1961 पूर्व नाजी नेता एडोल्फ इचमैन को पंद्रह आपराधिक आरोपों में दोषी पाए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसमें मानवता के खिलाफ युद्ध अपराध और अपराध शामिल हैं।

1961 बीबीसी श्रृंखला, कॉमेडी प्लेहाउस में पहला एपिसोड प्रस्तुत किया गया।

1965 बांग्लादेश में गंगा नदी के तट पर आये चक्रवात में 15,000 लोगों की मौत हुई।

1966 दुनिया की सबसे बड़ी एनीमेशन कंपनी के संस्थापक वॉल्ट डिज़्नी का निधन हुआ।

1973 अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने मानसिक विकारों की डीएसएम- II की आधिकारिक सूची से समलैंगिकता को हटा दिया।

1973 अरब इसराइल युद्ध के चलते अरब तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक ने अमरीका को तेल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। जिससे तेल की क़ीमतें तीन डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर अचानक 11 डॉलर प्रति बैरल तक जा पहुंचीं।

1976 न्यूजीलैंड से स्वतंत्र हुआ समोआ संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना।

1991 जाने माने फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को सिनेमा जगत में उनकी उपलब्धियों के लिए स्पेशल ऑस्कर से नवाजा गया।

1995 यूरोपियन कोर्ट ऑफ़ जस्टिस ने बोस्मान शासन को सौंप दिया, जिससे यूरोपीय संघ में फुटबॉलरों को अपने अनुबंधों के अंत में एक यूईएफए फेडरेशन से दूसरे में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति मिल गई।

1997 राष्ट्रपति क्लिंटन ने अपने लेब्राडोर का नाम लिया, बडी वामुराई को 1940 में विलुप्त घोषित किए जाने के बाद खोजा गया।

2000 डिज्नी के स्वर्ग पियर होटल डिज़्नलैंड रिज़ॉर्ट में खोला गया।

2001 ग्यारह सालों तक बंद रहने के बाद दुनिया के एक अजूबे पीसा की मीनार को जनता के लिए फिर से खोला गया।

2005 एफ -22 रैप्टर, एक स्टील्थ लड़ाकू विमान जो संयुक्त राज्य वायु सेना ने दावा किया था कि किसी भी ज्ञात या अनुमानित लड़ाकू द्वारा बेजोड़ है, एक लंबी और महंगी विकास अवधि के बावजूद सेवा में प्रवेश किया।

2005 2005 अटलांटिक पावर आउटेज शुरू किया गया।

2007 पाकिस्तान में आपातकालीन नागरिक क़ानून लागू।

दिल्ली की चुनावी जंग में कौन सत्ता का ताज पहनेगा?

ललित गर्ग

दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए फरवरी 2025 या उससे पहले चुनाव होने की संभावनाओं को देखते हुए राजनीतिक हलचलें एवं सरगर्मियां उग्र हो गयी है। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की तैयारी में जुट गई है। वहीं, भाजपा और कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटी है। भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव दूसरे प्रांतों की ही भांति बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के लड़ने का मन बना चुकी है और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच रखेगी। पार्टी का मानना है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली में भाजपा के पास एक से एक मजबूत नेता हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नेता मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी के लिए पेश नहीं किया जा रहा है। भाजपा दिल्ली में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नए तरीके से चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है, वही कांग्रेस अपनी खोयी जमीन को हासिल करने के लिये जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित ही इस बार का दिल्ली चुनाव आक्रामक एवं संघर्षपूर्ण त्रिकोणात्मक होगा। आप, कांग्रेस एवं भाजपा की चुनावी जंग में कौन सत्ता का ताज पहनेगा, यह भविष्य के गर्भ है।

दिल्ली में भाजपा के लिए यह चुनाव चुनौतीपूर्ण होने के साथ संघर्षपूर्ण भी है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में, जहां पार्टी को शानदार प्रदर्शन की उम्मीद थी, उसे आम आदमी पार्टी से हार का सामना करना पड़ा। तब भाजपा को दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत करने से कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ। इसके बजाए, भाजपा अब चुनावी रणनीतियों में बदलाव कर रही है और अपनी शक्ति को पार्टी संगठन और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी लोककल्याणकारी योजनाओं के बल पर मजबूत करने का प्रयास कर रही है। यही कारण है कि दिल्ली भाजपा आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में केंद्र सरकार के काम और योजनाओं को जनता के बीच रखेगी। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि दिल्ली के लोग इससे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, खासकर जब बात विकास, सुरक्षा, चिकित्सा और शिक्षा जैसे मुद्दों की हो। अगर भाजपा बिना किसी प्रमुख चेहरे के चुनाव लड़ती है तो यह असमंजस की स्थिति बनने की संभावनाएं तो पैदा कर ही सकती हैं। दूसरी ओर, यह फैसला एक रणनीतिक कदम हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके अन्य प्रांतों की भांति दिल्ली में भी चमत्कार घटित हो सकता है।

भाजपा ने यह भी तय किया है कि दिल्ली की जनता को बताया जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ वादाखिलाफी की है, वे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और सड़कों की स्थिति में सुधार का वादा करके उन्हें जर्जर करते रहे हैं। भाजपा का मानना है कि मोदी सरकार की योजनाएं देशभर में सफलता प्राप्त कर रही हैं और इन्हें दिल्ली में लागू किया जाएगा। भाजपा को दिल्ली में हमेशा मिडिल और हाई मिडिल क्लास के लोगों की पार्टी माना जाता है। इसमें व्यापारिक समुदाय इसके कट्टर समर्थक हैं। लेकिन इस बार निचले तबको एवं गरीब लोगों के बीच उसे प्रभावी प्रयास करने होंगे। यह तो दिखता हुआ सच है कि दिल्ली में आप शासन में विकास अवरूद्ध हुआ है, पर्यावरण की समस्या उग्रतर हुई है, आप नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे एवं उनके नेता जेल यात्राएं की है। ऐसे अनेक गंभीर आरोपों के साथ भाजपा आप और उसके

नेताओं पर आक्रमक होकर चुनावी परिदृश्यों को बदल सकती है।

भाजपा ने कमर कस ली है और उसके नेता लगातार जनता के बीच जाकर बदलाव की अपील कर रहे है। इसके तहत इन दिनों जहां परिवर्तन सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, वहीं अगले हफ्ते से पूरी दिल्ली में परिवर्तन यात्राएं भी निकाली जाएंगी। इन यात्राओं के माध्यम से आम मतदाताओं से निजी तौर पर मिलते हुए, उनसे बात करते हुए उनको पार्टी के साथ जोड़ा जायेगा। उनके दु:ख-दर्द को सुना जायेगा। भाजपा का इतिहास रहा है कि वह आम जन तक पहुंचने के लिए ऐसी यात्राएं निकालती रही है एवं व्यक्तिगत संवाद स्थापित करती रही है। भाजपा नेता सतीश उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली में एक भ्रष्ट सरकार चल रही है लेकिन अब तो रंगदारी, वसूली, फिरौती और आम नागरिकों के बीच डर पैदा करने की भी कोशिश की जा रही है। इसके चलते दिल्ली की जनता अब सत्ता परिवर्तन के मूड में है और देशविरोधी मानसिकता वाली सरकार को इस बार विधानसभा से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। देखना है कि भाजपा के इन आरोपों का जनता पर कितना असर होता है।

निश्चित ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जमीन अभी भी मजबूत है। इसीलिये 2025 के चुनाव कांग्रेस एवं भाजपा के लिये चुनौतीपूर्ण होने वाले है। 2020 में हुआ विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थीं। वहीं भाजपा को महज 8 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस का लगातार दूसरी बार दिल्ली से सफाया हो गया था। इस बार के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद आतिशी मार्लेना राज्य की मुख्यमंत्री बनी हैं। आप नेताओं ने चुनाव अभियान प्रारंभ कर दिया है। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने का फैसला किया है। आप ने पिछले दो विधानसभा चुनावों में भारी अंतर से जीत हासिल की है। आप के आंतरिक सर्वेक्षण बताते हैं कि आप इस चुनाव में भी आसानी से जीत की ओर बढ़ रही हैं। इन स्थितियों में आप क्यों कांग्रेस या अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करें? आप अभी भी निम्न-मध्यम वर्ग और झुग्गी-झोपड़ियों वाले इलाकों में काफी लोकप्रिय है।

आप का वोट शेयर पहले की तुलना में बढ़ा है और कांग्रेस कमजोर हुई है। हालांकि, 2013 में अपने पहले चुनाव के बाद से आप का वोट शेयर लगातार बढ़ता रहा। जबकि पिछले दशक में कांग्रेस को वोट देने वालों की संख्या में काफी कमी आई है। आप ने 2013 में अपने आश्चर्यजनक प्रदर्शन के साथ, कुल मतदान का 29 प्रतिशत वोट प्राप्त किया था। पार्टी को 70 में से 28 सीटों पर जीत मिली थी। आप ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई थी। इससे कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 24.5 प्रतिशत और सिर्फ आठ सीटों के साथ तीसरे स्थान पर आ गई थी। इसके बाद 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर क्रमश: 9.7 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत तक गिर गया। वहीं, आप ने 54.6 प्रतिशत और 53.6 प्रतिशत वोट शेयर के साथ भारी जनादेश हासिल किया। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एवं आप के बीच गठबंधन न होने का फायदा भाजपा को मिलता हुआ दिख रहा है। असल में आप के वोट कांग्रेस ही काटेगी।

कांग्रेस एक पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसका दिल्ली में व्यापक जनाधार रहा है। लेकिन वह 'जीत' और 'गठबंधन' की मृगमरीचिका में भटकती रही है, अपनी स्वतंत्र पहचान को खोती रही है। आखिर कमजोर सियासी बैशाखियों के सहारे वह कैसे जीत को सुनिश्चित कर सकती है? कांग्रेस की एक ओर बड़ी विडम्बना है कि वह जरूरी मुद्दों को उठाने की बजाय मोदी-विरोध का ही राग अलापती रही है। मुद्दों के बियाबान में भटकती और फिर स्टैंड बदलती नजर आती है तो इसके केन्द्रीय नेतृत्व एवं रणनीतिकारों पर तरस आती है। जबकि कांग्रेस के जमीनी नेताओं के पास रणनीति और जनाधार दोनों है, इसलिए उसके जमीनी नेता व्यक्तिवादी मिशन में सफल रहे, लेकिन कांग्रेस दिन ब दिन डूबती चली गई। राजनीतिक परिस्थिति वश कभी दो डग आगे तो चार कदम पीछे चलने को अभिशप्त हो गई। इन स्थितियों में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई करिश्मा या चमत्कार कर पायेगी, इसमें संदेह ही है।

शिवराज की धनखड़ ने क्यों की खिंचाई?

हरीश गुप्ता

राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ एक चतुर राजनीतिक हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत और बुद्धिमत्ता के बल पर यह पद पाया है। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने भले ही राजनीति छोड़ दी हो, लेकिन कोलकाता हो या नई दिल्ली-वह हमेशा चर्चा में रहे हैं। विपक्ष ने भले ही उनके खिलाफ अभी अविश्वास प्रस्ताव लाया हो, लेकिन तकनीकी कारणों से इस पर 2025 में संसद के बजट सत्र में ही विचार हो सकता है। इस विवाद के शुरू होने से पहले जगदीप धनखड़ ने पिछले मंगलवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सार्वजनिक रूप से खिंचाई करके राजनीतिक पर्यवेक्षकों को चौंका दिया। धनखड़ ने कहा कि किसान संकट में हैं, क्योंकि उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद चौहान से पूछा कि किसानों को दिए गए आश्वासन क्यों नहीं पूरे किए गए। शिवराज चुप रहे। तीन दिन बाद राज्यसभा में कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि क्या उसने किसानों की दुर्दशा के बारे में उपराष्ट्रपति की चिंताओं का संज्ञान लिया है? इस पर चौहान के जवाब देने से पहले, धनखड़ ने यह कहते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि वह महिलाओं के लिए लोकप्रिय योजना लाने वाले मंत्री से अपनी अपेक्षाएं व्यक्त कर रहे थे। 'मंत्री वहां मेरे साथ थे। मैंने किसानों को आश्वासन दिया कि लाड़ली बहना योजना लाने वाला मंत्री किसानों का लाड़ला बेटा बनेगा। मुझे उम्मीद है कि मंत्री इस योजना को साकार करेंगे। मैं आपको 'किसानों के लाड़ले' नाम दे रहा हूं,'धनखड़ ने कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षकों का मानना है कि राजनीति में बिना वजह कुछ नहीं कहा जाता। यह अलग बात है कि धनखड़ ने तीन दिन इस विषय पर चुप्पी साध ली। उन्हें सत्ता के बहुत करीब और संकटमोचक माना जाता है। कई लोगों का कहना है कि हरियाणा में भाजपा की बड़ी जीत में एक छिपा हुआ हाथ था। अकालियों को भाजपा की मदद करने के लिए चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े करने के लिए राजी किया गया, जबकि अभय चौटाला और मायावती ने भी यही खेल खेलने के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए।

केजरीवाल सुरक्षित ठिकाने की तलाश में- हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़ी जीत से भाजपा नए सिरे से उभरी है। इससे दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी(आप) बेहद चिंतित नजर आ रही है। 'आप' ग्यारह साल से सत्ता में है। इसने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को हराया है। लेकिन इस समय 'आप' खेमे में चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि 'आप' संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पारंपरिक नई दिल्ली सीट से हटने की योजना बना रहे हैं। जिस तरह से वह भाजपा और कांग्रेस से आए दल-बदलुओं को सीटें दे रहे हैं, उससे संकेत मिलता है कि पार्टी सकते में है। इसने अब तक घोषित 31 उम्मीदवारों में से 16 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया है, जबकि 21 दलबदलुओं को टिकट देकर उपकृत किया है। गौरतलब है कि 'आप' नेतृत्व ने अपने वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री राखी बिड़ला की सीट भी बदल दी है। तीन चुनावों के बाद अब निर्वाचन क्षेत्रों की अदला-बदली से पता चलता है कि पार्टी को फीडबैक मिल गया है कि कुछ हद तक उसने राजनीतिक जमीन खोई है। वैसे, 2013 से लगातार तीन जीत के बाद सत्ता-विरोधी लहर से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

भाजपा-अकाली दल फिर साथ-साथ!- पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हत्या की नाकाम कोशिश से अकाली दल और भाजपा के फिर साथ आने के रास्ते खोल दिए हैं। साफ संकेत मिल रहे हैं कि पंजाब में बादल के नेतृत्व वाले अकाली दल को कट्टरपंथी अपने नेता के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। उधर, 'आप' का ग्राफ गिर रहा है और कांग्रेस भी अपना घर नहीं संभाल पा रही है।

भारत के विदेश सचिव का बांग्लादेश दौरा

आनंद कुमार

भारत और बांग्लादेश के बीच तेजी से बिगड़ते संबंधों के बीच भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की हाल की ढाका यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का एक महत्वपूर्ण प्रयास थी। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत रिश्ते बांग्लादेश में बड़े राजनीतिक उथल-पुथल और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर बढ़ते तनाव के कारण हाल के दिनों में कमजोर हो गये हैं। विदेश सचिव की यह यात्रा, जो अगस्त में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के निष्कासन के बाद पहली उच्च-स्तरीय बातचीत थी, साझा चिंताओं को संबोधित करने और आपसी संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गयी। विदेश सचिव का यह दौरा वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के मद्देनजर भी बताया गया।

सच यह है कि बांग्लादेश में राजनीतिक संकट ने भारत के साथ उसके संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। शेख हसीना के इस्तीफे और भारत में उनके निर्वासन के बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार स्थिरता बनाये रखने में लगातार संघर्ष कर रही है। अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के आरोपों ने दोनों देशों के बीच के तनाव को और बढ़ा दिया है। हिंदू मंदिरों और सांस्कृतिक स्थलों पर, जिनमें ढाका स्थित भारतीय सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र भी शामिल है, हमलों की खबरों ने नयी दिल्ली में तीखी प्रतिक्रिया पैदा की। प्रमुख हिंदू साधु चिन्मय कृष्ण दास की देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी ने और अधिक अशांति फैलायी, जिससे बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए और ढाका में जवाबी प्रदर्शन हुए।

विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की नौ नवंबर की यात्रा का उद्देश्य इन बढ़ते मुद्दों को सुलझाना था। उन्होंने

अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जसीम उद्दीन, विदेशी मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत कराया। उन्होंने इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और उन पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी मामले को निष्पक्षता से देखे जाने की अपील भी बांग्लादेश से की। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इन बैठकों में विदेश सचिव ने एक स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील, लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया।

बांग्लादेश ने अपने यहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा की घटनाओं को स्वीकार किया और यह बताया कि विगत अगस्त से अक्तूबर के बीच अल्पसंख्यकों पर 88 हमले दर्ज किये गये, जिनमें से अधिकांश में हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया। बांग्लादेश ने इसकी भी पुष्टि की कि इन घटनाओं से जुड़े 88 मामले दर्ज किए गए हैं और कुल 70 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, बांग्लादेशी अधिकारियों ने इस हिंसा को व्यक्तिगत विवादों या राजनीतिक संबद्धताओं से उपजा बताते हुए इसके धार्मिक उद्देश्यों को कमतर करके आंकने की कोशिश की है।

विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की चर्चा तत्काल चिंताओं से आगे बढ़कर सीमा प्रबंधन, व्यापार, संपर्क, जल और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही। दोनों पक्षों ने विश्वास बहाली के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मोहम्मद यूनुस ने भारत-बांग्लादेश संबंधों को 'बहुत मजबूत' बताया और आपसी चिंताओं को दूर करने की प्रतिबद्धता दोहरायी, साथ ही भारत से 'बादलों को साफ करने' में मदद करने का आग्रह किया। विदेश सचिव मिस्त्री की यह यात्रा वस्तुत: वर्तमान भारत-बांग्लादेश संबंधों की जटिलताओं को रेखांकित करती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से शेख हसीना के नेतृत्व का समर्थन किया है और उनके शासन को एक स्थिर और विश्वसनीय साझेदार के रूप में देखा है। हालांकि, उनके निष्कासन ने नयी दिल्ली के दृष्टिकोण में पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पैदा कर दी है।

अपनी यात्रा के दौरान विक्रम मिस्त्री की संतुलित टिप्पणियों ने भारत की चिंताओं और बांग्लादेश की चुनौतियों, दोनों को स्वीकार करते हुए भारत के दृष्टिकोण में एक बदलाव का संकेत दिया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मौजूदा बांग्लादेश प्रशासन के साथ काम करने के लिए भारत उत्सुक है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके आपसी मतभेदों की वजह से वे संबंध न टूटें, जो सीमा के दोनों ओर के लाखों परिवारों को न सिर्फ सीधे-सीधे प्रभावित करते हैं, बल्कि नयी दिल्ली और ढाका के लिए भी जो संबंध रणनीतिक रूप से वाकई बहुत महत्वपूर्ण हैं।

अपने दौरे के अंत में विक्रम मिस्त्री ने पत्रकारों से कहा कि भारत ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के साथ काम करने की इच्छा जतायी, साथ ही, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और हाल ही में हुए हमलों को लेकर भारत की चिंता से अवगत कराया। दोनों पक्षों ने बिम्सटेक फ्रेमवर्क के तहत क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की बात पर सहमति जतायी।

भाजपा के खिलाफ 27 में फिर बदलेगा सियासी समीकरण

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर से सियासी समीकरण काफी तेजी के साथ बदल रहा हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की विरोध की हांडी नहीं पक पाने के कारण प्रदेश में एक बार फिर से नए सियासी समीकरण उभरते नजर आ रहे हैं। इस नये समीकरण में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी का अहम रोल हो सकता है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को दिये जाने की मांग का भी समर्थन कर रहे हैं। हो सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव के समय तक समाजवादी पार्टी कांग्रेसी पंजे से अपना हाथ छुड़ाकर ममता बनर्जी के कहने पर एक बार फिर से मायावती के साथ बुआ भतीजे वाला रिश्ता निभाते नजर आए। ऐसा होता है तो यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। यह संभावना इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों या महीनों से कांग्रेस समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। सपा-कांग्रेस के बीच दूरियां लगातार बढ़ने के साथ एक-दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक मंचों से बयानबाजी भी हो रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की नाकामी भी इसमें एक अहम कड़ी समझा जा रहा है। यही दूरियां ही हैं कि संसद के अंदर भी सपा-कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर मजबूती से एक साथ नहीं दिख रहे हैं ।सपा नेताओं का कहना है कि संभल मामले में उसके सांसद पर मुकदमे दर्ज किए जाने का कांग्रेस ने उस तरह विरोध नहीं किया जैसी उससे अपेक्षा थी। बताते हैं कि लोकसभा में फैजाबाद (अयोध्या) के सपा सांसद अवधेश प्रसाद की सीट पीछे होने पर भी दोनों दलों के रिश्तों में दरार आई है। सपा का मानना है कि सीटिंग प्लान पर बात के समय कांग्रेस ने उसे भरोसे में नहीं लिया। वहीं, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सदन में अदाणी मामले में उसे सपा का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। हाल यह है कि जेल में बंद सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने भी इंडिया ब्लॉक को जेल से एक संदेश भेजा है। इसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक को मुसलमानों पर हो रहे हमलों पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी लिखा कि संभल की घटना के जैसे ही रामपुर में हुए अत्याचार का मुद्दा भी संसद में उतनी ही मजबूती से

उठाना चाहिए।

कांग्रेस और सपा के बीच दूरियां तब और बढ़ गई जब सपा कि तरफ से कहा जाने लगा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस की जगह तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को दिए जाने पर सपा को एतराज नहीं है। बता दें लोकसभा चुनाव के बाद कई चुनावों में कांग्रेस की लगातार हार के बाद इंडिया गठबंधन में अंतर्विरोध बढ़ रहे हैं। उधर दूसरी तरफ चर्चा यह भी है कि यूपी की राजनीति एक बार फिर पलट सकती है। सपा और कांग्रेस के बीच आई दूरियों के बीच मायावती का रुख नई राजनीतिक समीकरणों को जन्म दे सकता है। बहराल, सपा नेताओं का कहना है कि संभल मामले में उसके सांसद पर मुकदमे दर्ज किए जाने का कांग्रेस ने उस तरह विरोध नहीं किया जैसी उससे अपेक्षा थी। बताते हैं कि लोकसभा में फैजाबाद (अयोध्या) के सपा सांसद अवधेश प्रसाद की सीट पीछे होने पर भी दोनों दलों के रिश्तों में असहजता पैदा हुई है। सपा का मानना है कि सीटिंग प्लान पर बात के समय कांग्रेस ने उसे भरोसे में नहीं लिया। वहीं, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सदन में अदाणी मामले में उसे सपा का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। रिश्तों में खटास का ही नतीजा है कि सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने कहा कि ममता बनर्जी वरिष्ठ नेता हैं। पार्टी हाईकमान भी यही चाहता है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी करें। सपा के प्रमुख महासचिव प्रो. रामगोपाल भी कह चुके हैं कि वे राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का नेता नहीं मानते हैं। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति में शामिल सपा के एक नेता बताते हैं कि कांग्रेस गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं है। उसके नेता चुनाव के वक्त ही सक्रिय होते हैं जिससे जनाधार नहीं बढ़ता। ऐसे में बेहतर होगा कि गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी करें। भाजपा को मात देने के लिए रणनीति के साथ जनता के बीच लगातार जुटे रहने की जरूरत है।

बात बीएसपी की की जाए तो हरियाणा व महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस व सपा के बीच बढ़ी दूरियों का सियासी लाभ बसपा को मिलने की उम्मीद है। पार्टी तेजी से बदले राजनीतिक घटना पर नजर बनाए हुए है। यदि कांग्रेस और सपा के बीच बात नहीं बनी तो इसकी वजह से बनने वाले तीसरे मोर्चा का बसपा अंग बन सकती है। जानकारों की मानें तो वर्तमान में पार्टी को अपना वजूद बचाने और देश की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को बरकरार रखने के लिए इसकी जरूरत भी है। बसपा के इतिहास पर नजर डालें तो वर्ष 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में उसे बहुमत मिला था। इससे पहले बसपा दूसरे दलों की मदद से सरकार बनाती रही, जिसका लाभ उसे लोकसभा चुनावों में भी मिलता गया। वर्ष 2012 में बसपा ने फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जो गलत साबित हुआ। यही हाल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ। 2019 में बसपा ने सपा के साथ गठजोड़ कर लोकसभा चुनाव लड़ा और 10 सांसदों वाली पार्टी बनी। हालांकि इसके बाद वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने से उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ गया। अब पार्टी की उम्मीदें तीसरा मोर्चा बनने पर टिकी हैं। वैसे तो मायावती सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों दलों को एक मंच पर ला सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो कांग्रेस को दरकिनार कर अगर तीसरा मोर्चा बना तो ममता बनर्जी उसकी निर्विवाद नेता बन सकती हैं। पहले उन्हें मायावती से चुनौती मिलने के जो समीकरण बने थे, वो बीते चुनावों में बसपा के लगातार घटते जनाधार की वजह से ध्वस्त हो चुके हैं। अब बसपा को अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ सकता है। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने पुराने बसपाइयों को भी वापस आने का बुलावा दिया है।

चीन ने भारत के पड़ोसियों में पैठ बना ली

हर्षा कक्कड़

एशिया में भारत और चीन प्रतिस्पर्धी हैं। भारत इस क्षेत्र का एकमात्र देश है जिसने चीनी सेना को उसके रास्ते में ही रोक दिया है। यह बी.आर.आई. को स्वीकार करने से भी इंकार करता है, जिसमें वे मंच भी शामिल हैं जहां दोनों देश संयुक्त रूप से भाग लेते हैं। लंबी बातचीत के बाद दोनों देश लद्दाख में पीछे हट गए। डी-एस्केलेशन और डी-इंडक्शन अभी भी कुछ दूरी पर हैं। हालांकि ऐसा प्रतीत हो सकता है कि शांति संभवत: कोने में है। मुख्य रूप से बदलती वैश्विक गतिशीलता के कारण, भारत इस बात से अवगत है कि चीन एक बड़ा खतरा है और वह अपनी चौकसी को कम नहीं होने दे सकता। भारतीय क्षमता और बुनियादी ढांचे का विकास काफी हद तक चीनी सैन्य खतरों का मुकाबला करने के लिए है। हालांकि चीन को सैन्य और आर्थिक रूप से संभालना एक पहलू है, लेकिन चिंता का विषय भारत के पिछवाड़े दक्षिण एशिया में बढ़ता चीनी प्रभाव है। यह भारत की सुरक्षा पर असर डालने की क्षमता रखता है। चीन द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण बहुत व्यापक हैं, जिनमें आर्थिक, शैक्षिक और कन्फ्यूशियस मॉडल को बढ़ावा देना शामिल है, जो अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। आर्थिक रूप से, भारत को छोड़कर दक्षिण एशिया के सभी देश चीनी बी.आर.आई. (बैल्ट रोड इनिशिएटिव) के सदस्य हैं। चीन द्वारा बिना किसी पूर्व शर्त के दिए गए ऋण ने इन देशों को बीजिंग का ऋणी बना दिया है। वर्तमान में, पाकिस्तान पर चीन का 72 प्रतिशत, श्रीलंका का 57 प्रतिशत, मालदीव का 68 प्रतिशत, नेपाल का 27 प्रतिशत और बंगलादेश का 24 प्रतिशत बकाया है। विश्व बैंक जैसे वैश्विक ऋणदाताओं से किसी भी ऋण के लिए, इन देशों को चीन से ऋण पुनर्गठन की आवश्यकता होगी, जो इसे अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है। श्रीलंका का मामला सर्वविदित है जहां चीन ने केवल तभी कार्रवाई की जब भारत ने नेतृत्व किया। विश्व स्तर पर, चीन ने कभी भी अपने ऋणों को देशों की प्रकृति और न ही उन परियोजनाओं के आधार पर तय किया है जिनके लिए वे मांगे गए हैं। इस प्रकार, पश्चिमी संस्थानों द्वारा सवाल उठाए गए या मानवाधिकारों के लिए स्वीकृत राष्ट्र चीनियों को पसंद करते हैं। एक बार फंसने के बाद, देश चीन का आभारी हो जाता है और समय के साथ वैश्विक मंचों पर उसका समर्थन करने के लिए मजबूर हो जाता है। चीन द्वारा शोषण किया जा रहा एक अन्य उपकरण शिक्षा है। यह 1996 में स्थापित चीन छात्रवृत्ति परिषद के माध्यम से छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। वर्तमान में यह पाकिस्तान से 7,100, श्रीलंका से 100, बंगलादेश से 55 और नेपाल और मालदीव से 75-75 छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति देता है। सरकार बदलने पर बंगलादेश से संख्या बढ़ सकती है। छात्रवृत्ति पर शामिल होने वाले सभी छात्रों को एक फाऊंडेशन कार्यक्रम से गुजरना आवश्यक है जो भाषा दक्षता और सांस्कृतिक अनुकूलन पर केंद्रित है। इसके अलावा कन्फ्यूशियस संस्थान, कक्षाएं और संस्थानों में मंदारिन भाषा का शिक्षण भी है। वैश्विक स्तर पर 498 कन्फ्यूशियस संस्थान और 773 कन्फ्यूशियस कक्षाएं हैं, जिनमें से 14 दक्षिण एशिया में हैं। चीनी सरकार द्वारा दक्षिण एशिया के कई स्कूलों में मंदारिन शिक्षण प्रायोजित किया जाता है। ये संस्थान चीनी भाषा सिखाने के अलावा चीनी संस्कृति और इतिहास का भी प्रचार-प्रसार करते हैं। आंतरिक रूप से, इसके अपने सोशल मीडिया नैटवर्क, वीबो और वी-चैट पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। 'ग्लोबल टाइम्स', 'चाइना डेली', 'पीपुल्स डेली' और 'चाइना ग्लोबल टैलीविजन नैटवर्क' जैसे चीनी सी.सी.पी. नियंत्रित मीडिया आऊटलेट अंग्रेजी के अलावा, हिंदी, बंगाली, उर्दू और तमिल में खाते संचालित करते हैं। अकेले ड्क्षहदी फेसबुक पेज पर 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं। चीनी दूतावास भारत में कई प्रिंट मीडिया नैटवर्क में पूरे पेज के विज्ञापन खरीदता है। इनमें से प्रत्येक चीनी विकास, विचारों और सांस्कृतिक उपलब्धियों को बढ़ावा देता है। यह 'समुद्र तक पहुंचने के लिए नाव उधार लेने' की चीनी रणनीति पर आधारित है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवाणी अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर

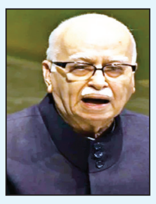

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को यहां अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि आडवाणी चिकित्सकों की निगरानी में हैं और उनकी हालत 'स्थिर' है। वह न्यूरोलॉजी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. विनीत सूरी की देखरेख में हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री (96) को करीब दो दिन पहले अस्पताल लाया गया था। उन्हें इस साल की शुरुआत में भी इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि आडवाणी को अभी अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया है। लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर, 1927 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था। बीती 8 नवंबर को ही आडवाणी ने अपना 98वां जन्मदिन मनाया है। आडवाणी साल 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री और 1999 से 2004 तक केंद्रीय गृह मंत्री रहे।

केरल के विपक्षी सांसदों का संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन

नईदिल्ली। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत केरल के विपक्षी सांसदों ने शनिवार को वित्तीय मांग को लेकर संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार वायनाड को विशेष पैकेज देने से इनकार कर रही है। हमने गृह मंत्री से अनुरोध किया है, हमने प्रधान मंत्री को लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह बड़े पैमाने पर तबाही देखी गई है और वहां कांग्रेस की सरकार है। वे केंद्र से मदद मांग रहे हैं और फिर भी दोनों मामलों में केंद्र सरकार राजनीति के कारण पीड़ितों को उनका हक नहीं दे रही है। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि वे भारत के नागरिक हैं। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। केरल आपदा के बाद के हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांग रहा है। इससे पहले बाढ़ से अस्त-व्यस्त हो चुके केरल के वायनाड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की थी।

संविधान के तहत बनी संस्थाओं को किया जा रहा कमजोर

नईदिल्ली। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणियों पर उन पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार के दौरान संविधान के तहत गठित सभी संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हम क्यों कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है? संविधान के तहत बनी संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, यह खतरा है। गहलोत ने आगे आरोप लगाया कि संविधान पर खतरा मंडरा रहा है और सरकार द्वारा बिना किसी बहस के पारित किए जा रहे विधेयकों से अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है। गहलोत ने आगे कहा कि कई सरकारें बदलीं। बदलाव और संवैधानिक संशोधन होते रहे हैं लेकिन संविधान पर मंडराते खतरे को लेकर फर्क है। आज संविधान बचाओ दिवस मनाया जा रहा है तो फिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन के समय कुछ ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई गई होंगी।

केजरीवाल ने शाह को लिखा पत्र, मिलने का मांगा समय

नईदिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर शनिवार को अमित शाह को पत्र लिखा और दिल्ली में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गृह मंत्री से मिलने का समय मांगा। केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में चिंताजनक कानून-व्यवस्था को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर हमला बोला था और कहा था कि अगर उनकी पार्टी की सरकार दिल्ली पुलिस पर नियंत्रण रखती तो स्थिति अलग होती। करोल बाग में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक पदयात्रा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वह केंद्र को शहर में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूर करने के लिए जनता के साथ एक आंदोलन शुरू करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में अपराध में वृद्धि का हवाला देते हुए, केजरीवाल ने कहा, भारत के 19 मेट्रो शहरों में से दिल्ली महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर एक पर है। हत्या के मामले में दिल्ली नंबर वन. दिल्ली में रंगदारी वसूलने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं।

महायुति सरकार पर संजय राउत का निशाना

मुंबई। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत ने शनिवार को महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का जुलूस निकालना चाहिए और ईवीएम मंदिर बनाने का निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक के दौरान उन्हें नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मुख्यालय के सामने ईवीएम मंदिर के निर्माण की घोषणा करनी चाहिए। सबसे पहले वहां (नागपुर में) मुख्यमंत्री का जुलूस निकाला जायेगा। मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री को जुलूस निकालने से पहले उन्हें ईवीएम का जुलूस निकालना चाहिए और पहली कैबिनेट में उन्हें आरएसएस मुख्यालय के सामने ईवीएम का मंदिर बनाने का निर्णय लेना चाहिए। शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने कैबिनेट जिम्मेदारियों पर निर्णय नहीं ले पाने को लेकर नवगठित सरकार पर निशाना साधा।

अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश करेंगे

नईदिल्ली। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 16 दिसंबर सोमवार को लोकसभा में संविधान विधेयक, 2024 पेश करेंगे। इस संबंध में कहा गया है कि संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024: अर्जुन राम मेघवाल भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे। विधेयक को पेश करने के लिए भी।

पहला संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित है। दूसरा विधेयक दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित है। इस बीच, अर्जुन राम मेघवाल संघ राज्य क्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 भी पेश करेंगे ताकि संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया जा सके।

कई विपक्षी नेताओं ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पर सवाल उठाया है और कहा है कि यह अव्यावहारिक है और संघवाद पर हमला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आरएस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, एक राष्ट्र, एक चुनाव में कहा गया है कि यदि कोई राज्य सरकार छह महीने में गिर जाती है या अपना बहुमत खो देती है, तो क्या राज्य को शेष 4.5 वर्षों तक बिना सरकार के रहना होगा। किसी भी राज्य में चुनाव 6 महीने से अधिक के लिए स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। यदि एक राष्ट्र एक चुनाव पेश किया जा रहा है और किसी राज्य में सरकार 6 महीने में गिर जाती है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो क्या हम 4.5 साल तक बिना सरकार के रहेंगे? इस देश में यह संभव नहीं है... पहले सरकारें 5 साल का अपना पूरा कार्यकाल पूरा करती थीं, लेकिन आज कुछ सरकारें 2.5 साल में गिर जाती हैं और कहीं 3 साल में गिर जाती हैं।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने प्रस्तावित एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की और कहा कि यह विधेयक लोकतंत्र को कमजोर करता है। रमेश ने कहा, विधेयक संसद में पेश किया जाएगा और हम चाहते हैं कि इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए, जो इस पर चर्चा करेगी। पिछले साल पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट की थी, जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की एक राष्ट्र, एक चुनाव समिति को चार पन्नों का पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि हम विधेयक का विरोध करते हैं। 12 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद इसे संसद में पेश करने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि, संसद में पेश किए जाने से पहले ही इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस शुरू हो गई थी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई दलों ने इस विधेयक का विरोध किया, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के दलों ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि इससे समय की बचत होगी और देश भर में एकीकृत चुनावों का आधार तैयार होगा। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष सितम्बर में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य 100 दिनों के भीतर लोकसभा और विधानसभा चुनाव, शहरी निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराना है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में ये सिफारिशें प्रस्तुत की गई थीं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले की सराहना करते हुए इसे भारत के लोकतंत्र को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

भारतीय संविधान न सिर्फ सबसे बड़ा है, बल्कि दुनिया का सबसे खूबसूरत भी है: किरेन रिजिजू

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारतीय संविधान न सिर्फ सबसे बड़ा है, बल्कि दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान भी है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि हमारे शब्दों और कार्यों से भारत की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बनीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद संविधान की भावना को बरकरार रखा और इसके प्रमुख पहलुओं के आसपास योजनाएं लागू कीं।

किरेन रिजिजू ने कहा कि भारतीय संविधान दुनिया के सभी संविधानों में सबसे समावेशी है। उन्होंने कहा कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने की अनुमति देता है और प्रत्येक नागरिक को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। रिजिजू ने कहा कि संविधान की विभिन्न धाराएं अल्पसंख्यकों को भी समान अधिकारों का आनंद लेने में सक्षम बनाती हैं। रिजिजू ने कहा कि भारतीय संविधान न सिर्फ सबसे बड़ा है, बल्कि दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान भी है।

भाजपा नेता ने कहा कि मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां मैंने हवाई जहाज पहले देखा है और कारें बाद में क्योंकि मेरे सांसद बनने के बाद ही कारों के लिए सड़कें बनीं। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने मुझे उस स्थान पर बैठने का अवसर दिया जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बैठे थे। जब मैं इस देश का कानून मंत्री बना। कानून मंत्री का पद संभालने से पहले मैंने सबसे पहले यह समझने की कोशिश की कि बाबा साहब अंबेडकर क्या सोचते थे, उनके मन में ऐसी कौन सी बातें और विचार थे जो वे नहीं कर सके।

उन्होंने कहा कि पहली बात जो मेरे दिमाग में आई वह यह थी कि बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के पहले कानून मंत्री बने लेकिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इस पर अक्सर लोगों के सामने चर्चा नहीं होती। मैंने वह पत्र पढ़ा जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने पंडित नेहरू जी को लिखा था, जो प्रधान मंत्री थे। उन्होंने कहा कि एक नैरेटिव रचा जा रहा है। सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस इन यूरोपियन यूनियन

के सर्वे के मुताबिक यूरोपियन यूनियन में 48 फीसदी लोग भेदभाव का शिकार हुए हैं। इनमें से अधिकांश इस्लाम को मानने वाले मुसलमान हैं। फ्रांस में अनेक भेदभाव संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की गईं। उसमें बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सिर पर स्कार्फ, बुर्का पहनने वालों पर आपत्ति जताई है और कहा है कि यह भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है. स्पेन में मुसलमानों के खिलाफ आंतरिक घृणा अपराध की घटनाएं इतनी ज्यादा हैं, इस बात का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल है, बांग्लादेश में क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में सिखों, हिंदुओं, ईसाइयों के साथ क्या हुआ है, तिब्बत हो या म्यांमार, श्रीलंका हो या बांग्लादेश, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, जुल्म हो तो क्या। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के विरुद्ध या कोई समस्या उत्पन्न होने पर वे सबसे पहले जिस देश में सुरक्षा मांगने आते हैं वह भारत है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि इस देश में अल्पसंख्यकों की कोई सुरक्षा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचे, मैं ये बात किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं। ये मैं देश के लिए कह रहा हूं।

लोकसभा में भाजपा पर बरसे राहुल गांधी

नईदिल्ली। भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान लोकसभा नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपना भाषण भाजपा के नहीं बल्कि आरएसएस के विचारों की आधुनिक व्याख्या करने वाले सर्वोच्च नेता के कथन को उद्धृत करके शुरू करना चाहता हूं, जो भारत के संविधान के बारे में और उनके विचार से भारत को कैसे चलाया जाना चाहिए, के बारे में कहते हैं - भारत के संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। मनुस्मृति वह धर्मग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए वेदों के बाद सबसे अधिक पूजनीय है और जिससे हमारी प्राचीन संस्कृति, रीति-रिवाज, विचार और व्यवहार का आधार बना है। इस पुस्तक ने सदियों से हमारे राष्ट्र की आध्यात्मिक और दैवीय यात्रा को संहिताबद्ध किया है। आज मनुस्मृति ही कानून है। राहुल ने दावा किया कि ये सावरकर के शब्द हैं...सावरकर ने अपने लेखन में स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस पुस्तक से भारत चलता है, उसे इस पुस्तक से हटा दिया जाना चाहिए। इसी बात को लेकर लड़ाई है। सत्तापक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप संविधान के संरक्षण की बात करते हैं तो आप अपने नेता सावरकर की खिल्ली उड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे (सत्ता पक्ष) पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने नेता के शब्दों पर कायम हैं? क्या आप अपने नेता के शब्दों का समर्थन करते हैं? क्योंकि जब आप संसद में संविधान की रक्षा के बारे में बोलते हैं, तो आप सावरकर का उपहास कर रहे होते हैं, आप सावरकर को गाली दे रहे होते हैं, आप सावरकर को बदनाम कर रहे होते हैं। कांग्रेस नेता ने साफ तौर पर कहा कि किसान एमएसपी मांगते हैं, लेकिन सरकार कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पहले भाषण में युद्ध के विचार का वर्णन किया, मैंने महाभारत का वर्णन किया, कुरुक्षेत्र का वर्णन किया। आज भारत में युद्ध हो रहा है।

खेल
प्रमुख समाचार

बारिश के कारण पहले दिन का खेल जल्दी समाप्त

ब्रिस्बेन। लगातार बारिश के कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल समाप्त हो गया है। मैच के शुरुआती दिन सिर्फ 13.2 ओवर का खेल ही हो सका। स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 28 रन बनाए हैं। उस्मान ख्वाजा 19 रन और नाथन मैकस्वीनी चार रन बनाकर नाबाद हैं। गाबा टेस्ट के पहले दिन बारिश के कारण बार-बार खेल बाधित हुआ। पहली बार 5.3 ओवर के बाद बारिश के कारण 20-25 मिनट का खेल बर्बाद हुआ था। फिर 13.2 ओवर के बाद एक बार फिर खेल को रोकना पड़ा।

शुरुआती दिन पहले सत्र में फिर भी कुछ खेल संभव हुआ, लेकिन लंच ब्रेक से पहले ही बारिश दोबारा शुरू हुई और मैच को रोकना पड़ा। दूसरे सत्र का खेल पूरी तरह धुल गया था, लेकिन इसके बाद भी स्थिति नहीं बदली और अंपायर ने स्टंप का फैसला किया। पहले दिन बारिश के खलल के कारण अब दूसरे दिन 98 ओवर फेंके जाएंगे और मैच तय समय से आधे घंटे पहले शुरू होगा। यानी दूसरे दिन का मुकाबला भारतीय समयानुसार, सुबह 5:20 बजे शुरू होगा।

इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने इस मैच के लिए प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए। रविचंद्रन अश्विन और हर्षित राणा को बाहर किया गया। उनकी जगह रवींद्र जडेजा और आकाश दीप को टीम में वापसी हुई। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम में एक बदलाव है। स्कॉट बोलैंड की जगह जोश हेजलवुड को शामिल किया गया। बारिश से दूसरे सत्र का खेल पूरी तरह धुल गया है। शनिवार को सिर्फ 13.2 ओवर का खेल हो सका है। कवर्स से पिच को ढका गया है। गाबा में मैदान सुखाने की अच्छी व्यवस्था है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

फरवरी में सस्ता हो सकता है लोन?

नईदिल्ली। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर नवंबर में घटकर 5.48% पर आ गई है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 2-6% के लक्ष्य दायरे के भीतर है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस गिरावट के चलते फरवरी 2025 में होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआई रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर सकता है। यदि ऐसा होता है, तो लोन की ब्याज दरों में कमी आ सकती है, जिससे ईएमआई पर बोझ कम होगा और कर्ज लेना सस्ता हो सकता है। खाद्य कीमतों में गिरावट और अनुकूल आधार प्रभाव के कारण यह सुधार संभव हुआ है। कोर मुद्रास्फीति, जो मुख्य मुद्रास्फीति से खाद्य और ईंधन को अलग करती है, भी नवंबर में घटकर 3.7% पर आ गई, जो अक्टूबर में 3.8% थी। वहीं, समग्र मुद्रास्फीति अक्टूबर में 6.2% थी।

खुदरा महंगाई दर घटकर 4.7-4.8% पर आ जाएगी

नई दिल्ली। भारत की हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा महंगाई वित्तीय वर्ष 2025 में 4.7-4.8 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अनुकूल सांख्यिकीय आधार, खाने-पीने की चीजों में कमी और स्थिर वैश्विक कमोडिटी कीमतों से राहत मिल सकती है। टमाटर, प्याज और आलू की नई फसल की आवक अधिक मंडी आवक में परिलक्षित हुई है, जिससे आपूर्ति दबाव कम हुआ है। दिसंबर के आंकड़ों से सब्जियों की कीमतों में और सुधार का संकेत मिलता है, जबकि अनुकूल मिट्टी की नमी और जलाशय के स्तर से मजबूत रबी फसल का भी अनुमान है। इसके अलावे, स्थिर वैश्विक खाद्य और ऊर्जा कीमतों से निकट भविष्य में महंगाई को जोखिम कम हो सकता है।

जमानत मुक्त ऋण की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों के लिए जमानत-मुक्त ऋण सीमा को 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। यह फैसला एक जनवरी, 2025 से प्रभावी होगा। इस कदम का उद्देश्य बढ़ती इनपुट लागत के बीच छोटे और सीमांत किसानों को मदद पहुंचाना है। नए निर्देश में देश भर के बैंकों को प्रति उधारकर्ता दो लाख रुपये तक का कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए ऋण देने की मार्जिन की आवश्यकता को माफ करने का निर्देश दिया गया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय बढ़ती लागत और किसानों के लिए ऋण सुलभता में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए लिया गया है। बयान में कहा गया है कि इस उपाय से 86 प्रतिशत से अधिक छोटे और सीमांत भूमिधारक किसानों को काफी लाभ होगा। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे दिशानिर्देशों को शीघ्रता से लागू करें तथा नए ऋण प्रावधानों के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करें।

जेएसडब्ल्यू स्टील को कोर्ट से राहत, मिलें 4 हजार करोड़

नईदिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसने उच्चतम न्यायालय की मंजूरी मिलने के बाद पूर्ववर्ती भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड की 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति जेएसडब्ल्यू स्टील को वापस कर दी है। जेएसडब्ल्यू स्टील कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत दिवालिया हो चुकी कंपनी भूषण स्टील की संपत्तियों के लिए सफल समाधान आवेदक थी। इन संपत्तियों को पहले संघीय जांच एजेंसी ने भूषण स्टील एंड पावर और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ एक जांच में कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी करने के आरोपों पर धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति की वापसी की गई। शीर्ष न्यायालय ने बुधवार को ईडी के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

ट्रंप बढ़ाएंगे टैरिफ, भारत का क्या होगा ?

भरत झुनझुनवाला

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि यदि ब्रिक्स देश अपनी अलग मुद्रा बनाने का प्रयास करते हैं, तो सभी सदस्य मुल्कों पर 100% आयात कर लगा दिया जाएगा। यह धमकी निष्प्रभावी है, क्योंकि ब्रिक्स देशों द्वारा एक अलग मुद्रा बनाना संभव नहीं। यूरोपीय यूनियन ने साझा मुद्रा यूरो बनाने के साथ-साथ सभी देशों के नागरिकों को एक दूसरे के यहां जाकर काम करने की छूट भी दी थी। ब्रिक्स के सदस्य- भारत, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और दूसरे देश इस तरह की छूट नहीं देंगे। ऐसे में अलग करेंसी नहीं बनाई जा सकती। इसके बाद भी ट्रंप द्वारा आयात कर बढ़ाने की बात गंभीर है।

ट्रंप ने भारत को आयात कर का राजा बताया है और मेक्सिको व कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही है। याद करें, ट्रंप के पिछले दौर में भारत के कई सामान को जनरल सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेस से हटा दिया गया था। इसके तहत, बिना आयात कर दिए अमेरिका में प्रवेश की छूट थी। नए कार्यकाल में ट्रंप निश्चित तौर पर सभी देशों पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ाएंगे, ताकि अमेरिका में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिले।

ट्रंप के इस कदम का भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमारे आईटी, दवा, कपड़े और जूते जैसे निर्यात प्रभावित होंगे। एच1बी वीजा में कटौती से भारतीय नागरिकों के लिए अमेरिका में काम करना कठिन हो जाएगा। उनके द्वारा भारत को रेमिटेंस कम भेजी जाएगी। ट्रंप द्वारा अमेरिकी कंपनियों को अमेरिका में ही उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके कारण विश्व की पूंजी का अमेरिका की तरफ पलायन होगा। इन तथ्यों को देखते हुए

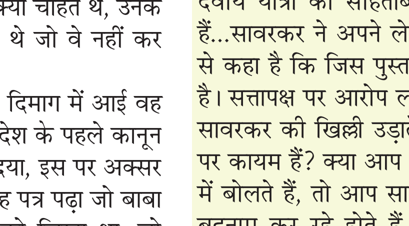

यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ने अनुमान लगाया है कि ट्रंप के कदमों के कारण भारत की विकास दर में 0.5% की गिरावट आ सकती है।

कयास लगाया जा रहा है कि ट्रंप के निशाने पर मुख्य रूप से चीन और रूस हैं, भारत नहीं। सामरिक दृष्टि से यह बात सही है। भारत मूल रूप से अमेरिका के साथ है। ट्रंप के निशाने पर चीन इसलिए है क्योंकि वह भारी मात्रा में अमेरिका को माल का निर्यात करता है। इससे अमेरिकी उद्योग ठंडे पड़े हुए हैं। ट्रंप को सामरिक समस्या कम और सभी देशों से होने वाले आयातों से समस्या ज्यादा है। इसलिए ऐसा सोचना सही नहीं कि ट्रंप, चीन पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ाएंगे, जबकि भारत को छोड़ देंगे। ट्रंप का मूल उद्देश्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और इस हिसाब से भारत व चीन एक बराबर हैं।

ट्रंप की पॉलिसी विदेशी व्यापार के सिद्धांत के विपरीत है और टिकाऊ नहीं होगी। विदेशी व्यापार इसलिए किया जाता है कि जो देश जो माल सस्ता बना सकता है, उसका उत्पादन करे और दूसरे उससे खरीदें। जैसे- भारत में बासमती चावल का उत्पादन सस्ता है, जबकि अमेरिका में अखरोट का। ऐसे में भारत चावल भेजे और अमेरिका अखरोट। ऐसे दोनों देशों के नागरिकों को सस्ता सामान मिल जाएगा। लेकिन, ट्रंप की पॉलिसी का नतीजा यह होगा कि अमेरिका को भारत और दूसरे देशों से जो सस्ती दवाएं, कपड़े, चावल वगैरह मिलते हैं, वे बंद हो जाएंगे। अमेरिकी नागरिकों को महंगा माल खरीदना पड़ेगा और उनके जीवन स्तर में गिरावट आएगी।

ट्रंप की नीति के जवाब में दूसरे देश भी चुप नहीं बैठेंगे। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा है कि उनका देश भी अमेरिकी सामानों के आयात पर टैक्स बढ़ाएगा। इससे अमेरिका का निर्यात घटेगा और साथ में रोजगार भी। फिर भी, संभव है कि अमेरिका में घरेलू बाजार के लिए उत्पादन बढ़ने से अमेरिकी नागरिकों को नौकरियां मिलें, लेकिन मेरा आकलन है कि यह प्रभाव देर से और न्यूनतम होगा। इसलिए, ट्रंप की पॉलिसी का अमेरिका में ही विरोध होगा, जैसे ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के बाद हो रहा है। व्यापार में अपने देश पर फोकस करने की यह पॉलिसी अगर सही होती, तो सारे देश ऐसा करके अपनी जनता का हित कर सकते थे।

मैं हूँ
बदलता
बस्तर
नया बस्तर देखने के लिए स्कैन करें
श्री अमित शाह
माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
संवाद-42449/122

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.